



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941

No. 351]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

केस सं. (एसजी)05/2019

**विषय:** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के तहत भारत में "सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच- प्रारंभिक जांच परिणाम- कार्यवाही

संदर्भ फा. सं. 22/5/2019-डीजीटीआर.—

**क. प्रस्तावना**

1. मैसर्स सेटलाइट टेक्नोलोजीज लिमिटेड ('एसटीसी') और मैसर्स बिड़ला फुरूकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लि. ('बीएफएल') (इसके बाद से इन्हें 'आवेदक'/'घरेलू उद्योग'/'डीआई' के रूप में भी कहा गया है) द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन नियमावली, 1997) (संक्षिप्तता के लिए "नियम") के नियम 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 (संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम") की धारा 8 ख के तहत मैसर्स टीएलसी लीगल एडवोकेट्स के माध्यम से समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को बढ़ते आयातों से हुई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति होने की आशंका के लिए रक्षोपाय हेतु भारत में "सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर" (इन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 (इसके बाद से इसे "कथित नियम" के रूप में भी कहा गया है) के नियम 5 के महानिदेशक (रक्षोपाय) (इसके बाद इन्हें "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष दिनांक 18.07.2019 को एक याचिका दाखिल की है। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वर्ष 2018-19 में काफी वृद्धि हुई है और हाल ही की अवधि में अर्थात् जनवरी, 19 से जून, 19 तक वृद्धि का स्तर जारी रहा है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि वे आयातों का मुकाबला करने और अपना बाजार अंश पुनः हासिल करने में सक्षम नहीं हैं जिससे उन्हें

अपना उत्पादन बंद करने अथवा अपने उत्पादन का आंशिक भाग निष्क्रिय रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस कारण से आवेदकों ने भी अपनी क्षति को कम करने के लिए एक तात्कालिक उपाय के रूप में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है।

#### **ख. अपनाई गई प्रक्रिया**

2. आवेदन और उसके साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य/विवरण/दस्तावेज की जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदन में कथित नियमावली के नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। अतः विचाराधीन उत्पाद के भारत में आयातों के खिलाफ दिनांक 23.09.2019 की जांच शुरूआत सूचना (एन ओ आई) के तहत एक रक्षोपाय जांच शुरू की गई थी। यह जांच शुरूआत सूचना (एन ओ आई) दिनांक 22.09.2019 के जीएसआर सं. 293 (ई) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

3. कथित नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के अनुसार दिनांक 23.09.2019 एनओआई की एक प्रति और घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका के अगोपनीय अंश (एन सी वी) की एक प्रति केन्द्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को उनके भारत में दूतावासों के माध्यम से और उक्त याचिका में उल्लिखित हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित की गई थी। इसके अलावा, उक्त नियमावली के नियम 6(4) के तहत यथानिर्धारित निर्यातकों/आयातकों/घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्तर दिए जाने वाली प्रश्नावली ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित की गई थी, जिसमें एन ओ आई जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने उत्तरों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

#### **ग. टिप्पणियां**

4. प्राधिकारी ने कथित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन और विधिवत प्रमाणित वित्तीय और अन्य रिकॉर्ड की ध्यानपूर्वक जांच की है। समान और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को उनके आयातों की वृद्धि के कारण से हुई गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की संभावना के लिए संरक्षण के लिए भारत में “सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर” के आयातों पर एक रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए वर्तमान जांच के लिए संगत विभिन्न कानूनों पर प्राधिकारी की प्रारंभिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं :-

#### **4.1 विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

4.1.1 संबद्ध उत्पाद “सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर” (“एस एम ओ एफ”) है। एस एम ओ एफ ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित है, जो लाइट के एक सिंगल स्पेशियल मोड कैरियर के रूप में पारेषण सुविधाएं प्रदान करता है और यह कतिपय बैंड में सिंगल पारेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानकीकृत सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर टाइप में नॉन-डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी 652), डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी 653), कट ऑफ शिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (जी 654) तथा नॉन जीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी 655 और 657) के साथ-साथ बेंड इंटेन्सिव सिंगल मोड फाइबर (जी 657) शामिल है- जैसा कि इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन (आई टी यू-टी), जो दूरसंचार प्रणालियों और विक्रेताओं के लिए एक वैश्विक मानक निकाय है, द्वारा परिभाषित किया गया है।

4.1.2 सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग यूनि-स्त्रूब और मल्टी-स्त्रूब स्ट्रैंडेड केबल, टाइट बफर केबल, आर्मर्ड और अन आर्मर्ड केबल, एडीएसएस और फिग-18 केबल, रिबन केबल, वेट कोर और ड्राई कोर केबल आदि सहित ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण के लिए होता है। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः हाई- डाटा रेट, लंबी दूरी और नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए यह मुख्यतः लॉग हॉल, मेट्रो एरिया नेटवर्क, सी ए टी वी, ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क (उदाहरण के लिए एफ टी टी एच) और यहां तक कि यथा लागू कम दूरी के नेटवर्क के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। मुख्य खपत ग्राम पंचायत, रक्षा (एनएफएस परियोजना) तथा डेटा सेन्टर की टेल्को की कनेक्टिविटी से 3जी/4जी/5जी द्वारा संचालित है।

4.1.3 संबद्ध उत्पाद सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर है, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 9001 10 00 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

#### **4.2 घरेलू उद्योग (डी आई)**

4.2.1 सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 (ख) की उप धारा (6) के खंड (ख) में घरेलू उद्योग (इसके बाद इसे “डी आई” के रूप में भी कहा गया है) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

(ख) "घरेलू उद्योग" से तात्पर्य ऐसे उत्पादों से है जो -

- i. भारत में समूची समान वस्तु अथवा एक प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु; अथवा
- ii. जिसका भारत में समान वस्तु अथवा एक प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का साझा आउटपुट मिलाकर भारत में उस वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है।

आवेदकों ने यह दावा किया है कि उनका साझा उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है और इस प्रकार से आवेदन विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अतः आवेदकों को घरेलू उद्योग माना जा सकता है।

केएफकेएम	2016-17	2017-18	2018-19	जन. से जून 2019	जन. से जून 2019 (वर्षिकीकृत)
कुल भारतीय उत्पादन	42612	47861	50590	22428	44856
प्रवृत्ति	100	112	118	105	105
कुल उत्पादन में घरेलू उद्योग के उत्पादन का %	***	***	***	***	***

4.2.2 घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उनके पास अन्य घरेलू निर्यातकों के उत्पादन के आंकड़े नहीं हैं। तथापि, अन्य सभी घरेलू निर्माता आयातित पूर्व निर्मित उत्पाद से उत्पादन करते हैं (जिसे किसी अन्य ज्ञात प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता) तदनुसार, कुल उद्योग उत्पाद का एक स्पष्ट अनुमान घरेलू उद्योग द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें मानक उद्योग मानदंड का पालन किया गया है कि 37 एफकेएम फाइबर 1 किग्रा. पूर्व निर्मित उत्पाद ~90% आफ्टर- ड्रॉ- यील्ड के साथ निर्मित किया जा सकता है। तदनुसार, आवेदकों ने कुल भारतीय उत्पादन की गणना करने के लिए आवेदकों द्वारा पूर्व निर्मित उत्पाद के आयातों को छोड़कर साइबेक्स एग्जिम सोल्यूसंस प्रा. लि. ("सी ई एस पी एल", संक्षिप्तता के लिए) से प्राप्त पूर्व निर्मित आंकड़ों के साथ उपरोक्त परिवर्तन अनुपात को प्रयुक्त किया गया है।

4.2.3 तदोपरांत, प्राधिकारी को मैसर्स फिनोलेक्स केबल लि. ("फिनोलेक्स", संक्षिप्तता के लिए) से दिनांक 30.09.2019 का पत्र प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन उत्पाद का एक घरेलू उत्पादक भी है, जिसने जांच शुरू करने का समर्थन किया है और अनंतिम शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने वर्ष 2016-17 से 2018 और अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 तक के उनके उत्पाद, क्षमता, बिक्री और वस्तुसूची की सूचना भी प्रस्तुत की है।

4.2.4 आवेदकों का उत्पादन भारत में उक्त उत्पादन के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है। तदनुसार, आवेदक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख की उप धारा (6) के खंड (ख) के तहत घरेलू उद्योग अथवा डी आई है।

### 4.3 जांच की अवधि (पीओआई)

4.3.1. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और कथित नियमावली तथा रक्षोपाय संबंधी करार और जीएटीटी के अनुरोध XIX में जांच की अवधि परिभाषित नहीं की गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी और हाल के समय की हांणी चाहिए ताकि विभिन्न संगत करारों, जैसे घरेलू बाजार की स्थिति, घरेलू उद्योग का निष्पादन आदि के आधार पर एक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या निर्यातों में वृद्धि के कारण वास्तव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की संभावना हुई है अथवा नहीं और इसीलिए रक्षोपाय शुल्क लगाने की जरूरत को स्पष्ट किया जाए। इस आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यों में, 2016-17 से 2018-19 और 2019-20 (जून, 2019 तक) का विश्लेषण अतिरिक्त रूप से किया गया है ताकि गंभीर क्षति, गंभीर क्षति की संभावना और नाजुक स्थिति की मौजूदगी की जांच की जाए।

### 4.4 सूचना का स्रोत

4.4.1 प्रारंभ में आवेदन में 2015-16 से 2018-19 और अप्रैल, 2019 से मई, 2019 तक की अवधि के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। तदोपरांत, इन्हें अद्यतन कर जून, 2019 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

4.4.2 घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए सौदा- वार आयात संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो कि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार से 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए प्राप्त किए गए थे। वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही के लिए घरेलू उद्योग ने प्रारंभ में एक द्वितीय

स्रोत से सौदा- वार आंकड़े प्रस्तुत किए थे। तथापि, बाद में प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से 2019-20 की प्रथम तिमाही के आंकड़े प्राप्त किए हैं जिन पर विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

4.4.3 वर्ष 2016-17 से 2018-19 और 2019-20 (जून, 2019 तक) की अवधि के लिए घरेलू उद्योग के संबंध में ही क्षति मापदंड से संबंधित इसी तरह के आंकड़े आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इन सभी आंकड़ों में विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

#### 4.5 प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता

4.5.1 घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में गोपनीय आधार पर कुछ सूचना प्रदान की है और यह अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय माना जाए। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन का एक अगोपनीय अंश भी प्रदान किया है, जो महानिदेशक (रक्षोपाय) जारी फाइल सं. डी- 22011/75/2009 के तहत जारी व्यापार नोटिस दिनांक 21.12.2019 के साथ पठित नियमावली के नियम 7 के तहत अपेक्षित है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस सूचना की गोपनीयता के अपने दावे को स्पष्ट करते हुए कारण प्रस्तुत किए हैं।

4.5.2 कथित नियमावली के नियम 7 के तहत आवेदक ऐसी सूचना को प्रकट न करने का चयन कर सकता है, जो कि गोपनीय प्रकृति की हो और तत्संबंधी अगोपनीय सारांश प्रदान किया गया हो। घरेलू उद्योग ने सूचना की गोपनीयता का दावा करने के कारणों का सारांश प्रस्तुत किया है और गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया है। चूंकि ये कारण कथित नियमावली के नियम 7 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, इसीलिए आवेदक द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे को एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

#### 5. आयातों में निरपेक्ष दृष्टि से वृद्धि

5.1.1 विचाराधीन उत्पाद भारत में विभिन्न देशों जिनमें चीन जन. गण., जापान, और कोरिया शामिल हैं, से आयात किया जा रहा है। विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख मात्रा चीन जन. गण. से आयात की जा रही है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि वर्ष 2018-19 में आयातों में अचानक तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक की यहां तक कि हाल की अवधि में भी उच्च स्तर पर जारी रहे। विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा 2018-19 में 9918 केएफकेएम से बढ़कर 2018-19 में 9918 केएफकेएम हो गई। घरेलू उद्योग (एसटीएल) ने भी 2018-19 के बाद से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इसलिए आयातों में वृद्धि के सही विश्लेषण और गंभीर क्षति के लिए घरेलू उद्योग को कुल आयातों से अलग किया गया है और केवल गैर- घरेलू उद्योग आयातों के लिए ही जांच की गई है जो नीचे सारणी में दर्शाया गया है :-

केएफकेएम में	2016-17	2017-18	2018-19	जन.'19- जून'19	जन.'19- जून'19 (वर्षिकीकृत)
कुल आयात	1903	2469	9918	4,268	8,536
प्रवृत्ति	100	130	521	521	449
आयात (गैर-घरेलू उद्योग)	1,903	2,469	7,066	3,267	6,534
प्रवृत्ति	100	130	371	371	343

5.1.2 आयातों (गैर- घरेलू उद्योग) में वृद्धि 2016-17 में 1903 केएफकेएम से 2018-19 में 7066 केएफकेएम हुई है और यह हाल की अवधि में भी (6534 केएफकेएम) वृद्धि के स्तर पर जारी रहे हैं। वर्ष 2016-17 के आधार वर्ष से वर्ष 2018-19 में 271 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

5.1.3 वर्ष 2018-19 की प्रत्येक तिमाही में और 2019-20 की प्रथम तिमाही में विगत वर्षों की तुलना में काफी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो नीचे दर्शाया गया है। आवेदकों ने यह प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में आयातों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी, जिसने घरेलू बाजार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तदोपरान्त आयातों में कमी आई है, तथापि, ये कमी भी उच्च स्तर पर नहीं रही और वृद्धि की प्रवृत्ति रही।

आयात (गैर- घरेलू उद्योग) केएफकेएम	प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
2017-18	769	545	540	615
2018-19	1244	2797	1436	1589
2019-20	1678			

## 5.2 आयातों में सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि

5.2.1 घरेलू उत्पादन के संबंध में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वर्ष 2016-17 से 2018-19 और जनवरी- जून, 2019 के बीच निरंतर वृद्धि पाई गई है और यह आधार वर्ष से और साथ ही विगत वर्ष के स्तर से तीन गुणा से अधिक हो गई है।

केएफकेएम में	2016-17	2017-18	2018-19	जन.'19- जून'19*	जन.'19- जून'19 (वर्षिकीकृत)
आयात (गैर- घरेलू उद्योग)	1,903	2,469	7,066	3,267	6,534
प्रवृत्ति	100	130	371	343	343
घरेलू उद्योग का उत्पादन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	114	120	103	103
घरेलू उद्योग के उत्पादन की % प्रवृत्ति के रूप में आयात	100	114	329	357	357

## 5.3 अप्रत्याशित विकास

5.3.1 न तो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के तहत और न ही उसके तहत बने नियमों के तहत महानिदेशक (रक्षोपाय) पर अप्रत्याशित विकास का विश्लेषण करने की कोई बाध्यता है, जिसके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है। विधिक प्रावधानों में न तो कोई ऐसे मानदंड शामिल हैं, जिनकी अप्रत्याशित विकास की पहचान के लिए पुष्टि की जानी चाहिए और न ही वे ऐसी कोई कार्यप्रणाली स्पष्ट करते हैं कि जिनका ऐसे अप्रत्याशित विकास के विश्लेषण में अनुसरण किया जाना चाहिए। तथापि, जी ए टी टी के अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपाय पर करार के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरणों के लिए यह बहुमत है कि वे “अप्रत्याशित विकास” की जांच करे, जिनसे आयातों में वृद्धि हुई है और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति हुई है। इस अपेक्षा को देखते हुए प्राधिकारी अपनी जांचों में “अप्रत्याशित विकास” के मामले की निरंतर जांच करते रहे हैं। अतः वर्तमान मामले में भी यह उपयुक्त समझा गया है कि अप्रत्याशित विकास अथवा परिस्थितियों की जांच की जाए जिनसे कि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसा करने के लिए, आवश्यक है कि पहले “अप्रत्याशित विकास अथवा परिस्थितियों” शब्द के आयातों को समझा जाए और इसके लिए डब्ल्यू टी ओ के अपील निकाय के विभिन्न नियमों के लिए एक संदर्भ दिए जाने की जरूरत है।

5.3.2 डब्ल्यू टी ओ के अपील निकाय ने **अर्जेन्टीना- फुटबियर (ईसी)**<sup>1</sup> मामले में यह पाया है कि इतनी वृद्धि की मात्रा में और ऐसी स्थितियों के तहत आयातों से घरेलू उत्पादकों को क्षति होने अथवा गंभीर क्षति होने की संभावना “अप्रत्याशित” होनी चाहिए। ऐसे मामले में, यह भी पाया गया था कि बढ़ते आयातों का कारण “अप्रत्याशित विकास” होना चाहिए। इसी प्रकार, **कोरिया डेयरी में डब्ल्यू टी ओ के अपील निकाय**<sup>2</sup> मामले में यह पाया गया कि अप्रत्याशित विकास ऐसे विकास हैं जो अप्रत्याशित अथवा प्रत्याशित नहीं हैं जब सदस्य ने अपनी बाध्यता को स्वीकार किया है। ऐसे मामले में यह भी स्वीकार किया गया था कि अप्रत्याशित विकास ऐसी परिस्थितियां हैं जिसे एक तथ्यपरक मामले के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। दूसरे मामले में, **यू एस- स्टील रक्षोपाय**<sup>3</sup> संबंधी पैनल ने यह निष्कर्ष दिया है कि कई घटनाओं का संग्राम एक अप्रत्याशित

<sup>1</sup> अपील निकाय रिपोर्ट, अर्जेन्टाइना- फुटबियर (ईसी), पैरा 90

<sup>2</sup> अपील निकाय रिपोर्ट, कोरिया-डेयरी पैरा 85 और 89

<sup>3</sup> यू एस- स्टील रक्षोपाय, पैरा 315

विकास के लिए आधार के रूप में शामिल हो सकता है। यह भी नोट किया गया था कि आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित विकासों का परिणाम हो सकती है अर्थात् यह ऐसा अप्रत्याशित विकास है, जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई है।

5.3.3 वर्तमान मामले पर उपर्युक्त जांच परिणामों को लागू करने से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि की अस्थायी प्रकृति, जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती है अथवा ऐसी गंभीर क्षति की संभावना में वृद्धि होती है, अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित और वास्तविक होनी चाहिए। जबकि आयातों में वृद्धि अपनी आय में आयातों पर आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शित होनी चाहिए, इसकी अनपेक्षित अथवा अप्रत्याशित प्रकृति पर जांच परिणाम प्रासंगिक होने चाहिए।

5.3.4 वर्तमान जांच में, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि वर्ष 2018-19 और जांच की अवधि में आयातों में अचानक से हुई वृद्धि वैश्विक बाजार में कतिपय अप्रत्याशित विकासों का परिणाम थी। अनेक विकासों का एक संगम है जैसे फाइबर उद्योग में वैश्विक अति क्षमता, अधिकांश फाइबर विनिर्माण वाले देशों में चीन द्वारा व्यापार उपायों को लागू करना/विस्तार करना, यूएसए, आस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा चीन से दूरसंचार उपकरणों/घटकों के आयातों पर लगाए गए नीति संबंधी प्रतिबंध, और अन्य गैर- वित्तीय/गैर-विनियामक प्रतिबंध, जो चीन से निर्मित फाइबर पर प्रमुख दूरसंचार आपरेटरों (विशेषकर पश्चिमी यूरोप और यू एस ए में दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा) के परिणामस्वरूप भारत में अचानक से आयातों का रुख हुआ है। यह अनुरोध किया गया है कि चीन का बाजार, जोकि ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा ग्राहक और उत्पादक है, अपनी अति क्षमता के कारण से मंदी और कम घरेलू मांग का सामना कर रहा है। इसके अलावा, चीन निर्मित ऑप्टिकल फाइबर यूएसए और अधिकांश यूरोप के देशों सहित कई पश्चिमी देशों में प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अनुमोदित नहीं है। अतः चीन के विनिर्माताओं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सीमित कर दिया है और अपने नजदीकी उभरते बाजारों में अपना उत्पादन उतारने पर मजबूर हैं।

5.3.5 इसके अलावा, चीन ने भारत, जापान और यू एस ए सहित अधिकांश ऑप्टिकल फाइबर विनिर्माण करने वाले देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। परिणामस्वरूप, चीन का बाजार, जोकि संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा ग्राहक है, अन्य देशों से निर्यातों के लिए अव्यवहार्य हो गया है। इन कारणों से चीन व अन्य देशों में निर्यातकों को अन्य व्यवहार्य निर्यात के विकल्प तलाशने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत चूंकि एक उभरता मांग बाजार है, अपने अधिक्य उत्पादन को उतारने के लिए निर्यातकों के लिए आसान लक्ष्य बन गया है।

5.3.6 रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही और दूसरी तिमाही से भारत में आयातों की अचानक से वृद्धि हुई। यह उस अवधि के साथ संयोग ही था कि जब चीन के बाजार में अन्य के साथ-साथ फाइबर विनिर्माण क्षमता में अचानक वृद्धि, चीन के मोबाइल के टेंडर में विलंब जैसे कारणों से क्षति आपूर्ति की समस्या शुरू हुई, जोकि चीन व विश्व में ऑप्टिकल फाइबर के सबसे बड़े ग्राहकों में से है। इसके अलावा, चीन के बाजार में मंदी के साथ ही, जो कि वैश्विक ऑप्टिकल फाइबर उत्पादन का करीब 50 प्रतिशत उपयोग करता है, अन्य देशों में विदेशी उत्पादकों की भी अधिक उत्पादन की समस्या है।

5.3.7 इस प्रकार, वर्ष 2018-19 के दौरान और हाल की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक और तीव्र वृद्धि विभिन्न वैश्विक मिश्रित घटनाओं के परिणाम से है, जो कि अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित थी। आयातों में यह वृद्धि होने से आयातित और घरेलू उत्पाद वाले विचाराधीन उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धी भागीदारी हुई, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ।

## 6. रक्षोपाय के प्रारंभिक निर्धारण के लिए कानूनी प्रावधान

6.1.1 आवेदकों ने अपने आवेदन में अनंतिम रक्षोपाय शुरू करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा वे अपने दिनांक 3.10.2019 के पत्र के तहत जांच की अवधि के अलावा वर्ष 2019-20 (जुलाई-सितंबर, 2019) की दूसरी तिमाही के डाटा से नाजुक परिस्थिति के साक्ष्यों के साथ आगे आए हैं और यह अनुरोध किया है कि अनंतिम शुल्क लगाने में विलंब से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

6.1.2 अधिनियम की धारा 8 ख (2) के तहत प्राधिकारी एक प्रारंभिक निर्धारण के आधार पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं कि आयातों में वृद्धि के कारण धारा 8ख (1) के तहत घरेलू उद्योग के लंबित निर्धारण के चलते गंभीर क्षति की संभावना है।

6.1.3 जी ए टी टी, 1994 के अनुच्छेद XIX के तहत रक्षोपाय को "विशेष उत्पादों के आयातों पर "विशेष उत्पादों के आयातों पर आकस्मिकता की कार्रवाई" के रूप में वर्णित किया गया है। इस तरह की तात्कालिकता अथवा आकस्मिकता

हमारे नगरपालिका कानूनों में भी अपनाई गई है। कतिपय नियमावली के नियम 9 के तहत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि जांच के लिए शीघ्र आगे की कार्रवाई करें और नाजुक परिस्थितियों में गंभीर क्षति होने अथवा गंभीर क्षति की आशंका के बारे में प्रारंभिक जांच परिणाम को दर्ज करें। नियमावली का संगत अंश नीचे दिया गया है :-

*“(1) महानिदेशक जांच के आयोजन के साथ और नाजुक परिस्थितियों में यथाशीघ्र आगे कार्रवाई करेंगे, वे गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका के बारे में एक प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।”*

6.1.4 “नाजुक परिस्थिति” शब्द को नियम 2 (ख) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

*“नाजुक परिस्थितियां” से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से है, जिनमें स्पष्ट साक्ष्य हैं कि आयात ऐसी बढ़ती मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में हुए हैं कि उनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका हुई है और अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने में विलंब से घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी।”*

6.1.5 नगरपालिका कानून में प्रावधान जी ए टी टी 1994 के तहत रक्षोपाय संबंधी करार की धारा 6 के अनुरूप हैं, जिसमें यह भी प्रावधान है कि नाजुक परिस्थितियों में, जहां विलंब होने से क्षति होगी, जिसे ठीक कर पाना कठिन होगा, कोई सदस्य किसी प्रारंभिक निर्धारण के अनुसरण में एक अनंतिम रक्षोपाय उपायों का सहारा ले सकता है कि इस बात का एक स्पष्ट साक्ष्य है कि आयातों में वृद्धि से गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने की आशंका है। अनुच्छेद 6 में यह भी प्रावधान है कि अनंतिम रक्षोपाय उपाय केवल 200 दिनों की अवधि के लिए लगाए जा सकते हैं, जिनके दौरान कि प्राधिकारी ने अनुच्छेद 2 के तहत 7 (जो अन्य के साथ-साथ गंभीर क्षति की जांच अपेक्षित निर्धारण से संबंधित हैं) और 12 के माध्यम से अपेक्षित विश्लेषण किया है। इसके अलावा, रक्षोपाय नियमावली के अनुच्छेद 6 और नियम 15 में शुल्क की वापसी का प्रावधान है, यदि समाप्त हुई जांच के आधार पर लगाए गए शुल्क पहले से लगाए गए अनंतिम शुल्क से कम है।

6.1.6 नगरपालिका कानून अधिनियम तथा नियमों और जी ए टी टी के तहत 2 रक्षोपाय संबंधी करार के प्रावधान के सम्मिलित पठन से माना गया है कि कानून में उपयुक्त मामलों में अंतरिम उपायों की तत्काल रिकॉर्डिंग के लिए विचार किया गया है। तदनुसार, आयातों की वृद्धि, गंभीर क्षति अथवा उसकी आशंका और नाजुक परिस्थितियों, का विश्लेषण यह जांचने के लिए किया गया है कि क्या वर्तमान मामला अनंतिम शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी “नाजुक परिस्थितियों” की श्रेणी में आता है।

## 7. गंभीर क्षति :

7.1.1 उपरोक्त से रक्षोपाय उपाय करने की सिफारिश करने के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम दिए जाने अपेक्षित हैं, यदि निम्नलिखित मौजूद हो :-

- i. आयातों की वृद्धि के साक्ष्य ;
- ii. ऐसे आयातों से गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने की आशंका है)
- iii. नाजुक परिस्थितियों की मौजूदगी, जहां विलंब से अपूरणीय क्षति होगी।

7.2 आयातों की वृद्धि के पहलु पर आगामी पैरा में विस्तार से दर्शाया गया है। आयात के आंकड़ों से स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया गया है कि आयातों से एक तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है; जो निरपेक्ष अर्थों में और सापेक्ष अर्थों में गंभीर क्षति परिस्थितियों का विश्लेषण इसके तहत से किया गया है।

7.3 “गंभीर क्षति” को अधिनियम की धारा 8 ख की उप धारा (6) में एक ऐसी क्षति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे एक घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की स्पष्ट और गहन आशंका है।

7.4 रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 4.2 (क) और सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुलग्नक में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि कतिपय सूचीबद्ध कारकों और अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका के निर्धारण के लिए मूल्यांकन किया जाए। तथापि, ये प्रावधान यह निर्दिष्ट नहीं करते जो ऐसे मूल्यांकन में प्रदर्शित होना चाहिए। इस संदर्भ में **अर्जेन्टाइना – फुटबियर (ई सी)<sup>4</sup>** के निर्णय के लिए संदर्भ दिया जाना चाहिए जिसमें अपील निकाय ने अनुच्छेद 4.1 (क) में “गंभीर क्षति” और अनुच्छेद 4.2 (क) में “सभी संगत कारक” के मूल्यांकन के लिए चर्चा करनी चाहिए और ऐसे मूल्यांकन के परिणाम 4.2 (क) में दिए गए हैं।

<sup>4</sup> अपील निकाय रिपोर्ट, अर्जेन्टाइना – फुटबियर (ईसी) पैरा 139

“(1) यह तभी है जब घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन ऐसे सभी संगत कारकों को देखते हुए किया गया है जिनका उस उद्योग की स्थिति से संबंध है, कि यह निर्धारण किया जा सकता है कि क्या उस उद्योग की स्थिति में एक महत्वपूर्ण समग्र क्षति ” हुई है। यद्यपि अनुच्छेद 4.2 (क) में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि कतिपय सूचीबद्ध कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह कि सभी अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि प्रावधानों से यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि क्या ऐसा मूल्यांकन प्रदर्शित किया जाए। स्पष्ट तौर पर ऐसा कोई मूल्यांकन भिन्न मामलों में भिन्न उद्योगों के लिए भिन्न होगा, जो विशेष मामले के रूपों और संबद्ध उद्योग की स्थिति के आधार पर होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन आवश्यक रूप से यह नहीं दर्शाता कि प्रत्येक कारक में ‘गिरावट’ आ रही है। एक मामले में, उदाहरण के लिए बिक्रियों, रोजगार और उत्पादकता में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है, जो उद्योग की स्थिति में ‘महत्वपूर्ण समग्र क्षति’ को दर्शाएगा और इसीलिए गंभीर क्षति के परिणाम को स्पष्ट करेगा। दूसरे मामले में, किसी कतिपय कारक में गिरावट नहीं भी आ रही हो लेकिन समग्र तस्वीर कभी भी उद्योग की “महत्वपूर्ण” समग्र क्षति को प्रदर्शित नहीं करती। इस प्रकार, एक तकनीकी जांच के अलावा, कि क्या एक मामला विशेष में सक्षम प्राधिकारियों ने सूचीबद्ध कारकों और अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया है, हम यह विश्वास करते हैं कि एक पैनल के लिए यह आवश्यक है कि रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1 (क) में ‘गंभीर क्षति’ की परिभाषा को ‘गंभीर क्षति’ के किसी निर्धारण की समीक्षा में शामिल किया जाए।

7.5 इसके अलावा, एक जांच परिणाम में यू एस - व्हीट ग्लूटेन<sup>5</sup> में पैनल में अपील निकाय द्वारा यह माना गया है, “गंभीर क्षति ” के तात्पर्य पर इसे व्यापक बनाया गया है।

‘[क] ऐसी महत्वपूर्ण समग्र क्षति का निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर संबद्ध रखने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में केवल घरेलू उद्योग की स्थिति के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है।

(हम) यह विचार नहीं करते कि जांचे गए प्रत्येक सिंगल फैक्टर में नकारात्मक प्रवृत्ति किसी भी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण समग्र क्षति की स्थिति होने के लिए आवश्यक है। इसके बजाय, यह प्रवृत्तियों और उनके पारस्परिक प्रभाव की समग्रता है, जिसको एक गंभीर क्षति निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः अनेक कारकों में इस तरह का बदलाव गंभीर क्षति के निर्धारण को अनिवार्यतः नहीं रोकेगा। यह जांच प्राधिकारियों पर है कि वह उनके समक्ष साक्ष्यों का आकलन करके उनको महत्व दे और एक पर्याप्त, तर्कसंगत और तार्किक स्पष्टीकरण दे कि ये तथ्य किए गए निर्धारण के समर्थन में कैसे हैं”

7.6 तदनुसार, अनंतिम शुल्क लगाने के विचार के लिए गंभीर क्षति, गंभीर क्षति की आशंका और नाजुक परिस्थितियों का विश्लेषण करने में, नियमों में उल्लिखित सभी कारकों और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका के निर्धारण के लिए संगत सभी कारकों पर विचार किया गया है, जैसा कि यहां नीचे उल्लेख किया गया है :-

#### क. बिक्री के स्तर में परिवर्तन

अलग-अलग ग्राहकों को आवेदकों की घरेलू बिक्रियों में विगत वर्षों की तुलना में काफी गिरावट आई है :-

(केएफकेएम)	2016-17	2017-18	2018-19	जन.'19 से जून '19	जन.'19 से जून '19 (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की घरेलू सम्मिलित घरेलू बिक्रियां (गैर-कैप्टिव/गैर-संबद्ध)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	65	48	31	31
आयात (गैर-घरेलू उद्योग)	1,903	2,469	7,066	3,267	6,534
प्रवृत्ति	100	130	371	343	343

उपरोक्त से यह देखा गया है कि 2016-17 में आयात 1903 केएफकेएम था और घरेलू उद्योग की बिक्रियां \*\*\* केएफकेएम थी। यह स्थिति 2018-19 में आयात बढ़कर 7066 केएफकेएम होने से उल्टी हो गई है और घरेलू उद्योग की बिक्रियां घटकर \*\*\* केएफकेएम हो गई हैं। घरेलू उद्योग को बाजार अंश से हुए नुकसान की पूर्ति आयातों में वृद्धि से हो गई है।

<sup>5</sup> पैनल रिपोर्ट, यू एस - व्हीट ग्लूटेन, पैरा 8.80 तथा 8.85।



**ख. घरेलू मांग में आयातों और घरेलू उत्पादकों का बाजार अंश**

आवेदकों ने यह प्रस्तुत किया है कि उनके पास अन्य भारतीय उत्पादकों के बिक्री के आंकड़े संलग्न नहीं हैं, इसलिए कुल भारतीय खपत की संख्या एक ऐसे निकाय सीआरयू की तिमाही रिपोर्ट से ली गई है, जो ऑप्टिकल फाइबर मार्केट सहित पण्य बाजार (कमोडिटी मार्केट) का अध्ययन और विश्लेषण करने में विशेषज्ञ है।

अलग-अलग ग्राहकों के लिए बाजार में अंश का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी की खपत (कैप्टिव/संगत पक्ष की बिक्री से अथवा आयातों से) कुल भारतीय खपत से अलग कर दी गई है जैसा कि सी आर यू द्वारा सूचित किया गया है और मांग में प्रतिशत अंश नीचे सारणी में दिया गया है :-

आंकड़े : \*\*\* केएफकेएम में

	2016-17	2017-18	2018-19	जन.'19 से जून '19	जन.'19 से जून '19 (वार्षिकीकृत)
सी आर यू के अनुसार भारतीय खपत	27062	32186	35197	17547	35094
अलग-अलग ग्राहकों के लिए भारतीय खपत (घरेलू उद्योग की कैप्टिव/संगत पक्ष की बिक्रियों और घरेलू उद्योग के आयातों को छोड़कर)	17,971	15,057	12,948	8,763	17526
आयात (गैर-घरेलू उद्योग)	1,903	2,469	7,066	3,267	2186
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां (प्रवृत्ति)	100	65	48	31	31
अलग-अलग ग्राहकों के लिए मांग में आयातों का अंश (गैर- घरेलू उद्योग) (घरेलू उद्योग की कैप्टिव/ संगत पक्ष की बिक्रियों और घरेलू उद्योग के आयातों को छोड़कर)	11%	16%	55%	37%	37%
अलग-अलग ग्राहकों के लिए मांग में घरेलू उद्योग के अंश की प्रवृत्ति (घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत और संगत पक्ष की बिक्रियों को छोड़कर)	100	77	67	31	31

**ग. उत्पादन के स्तर में परिवर्तन**

हाल की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2017-18 और 2018-19 की तुलना में काफी गिरावट आई है। यद्यपि, मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

उत्पादन (केएफकेएम)	2016-17	2017-18	2018-19	जन.' 19- जून 19	जन.' 19- जून 19 (वार्षिकीकृत)
एसटीएल (प्रवृत्ति)	100	115	123	117	117
बीएफएल (प्रवृत्ति)	100	111	109	62	62
कुल घरेलू उद्योग उत्पादन (प्रवृत्ति)	100	114	120	103	103

**घ. क्षमता उपयोग**

घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग इस प्रकार है :-

क्षमता उपयोग	2016-17	2017-18	2018-19	जन.' 19- जून 19	जन.' 19- जून 19 (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता (एफकेकेएम)	100	112	135	143	143
घरेलू उद्योग का उत्पादन (एफकेकेएम)	100	114	120	103	103
घरेलू उद्योग का उपयोग	100	103	89	73	73

घरेलू उद्योग को क्षमता उपयोग में गिरावट 2017-18 में \*\*\* से हाल की अवधि में \*\*\* आ गई है।

आवेदकों ने यह दावा किया है कि इस उद्योग के लिए अनुकूलतम क्षमता उपयोग करीब 100 प्रतिशत है, क्योंकि उत्पादन की कमी अथवा संयंत्र को पुनः शुरू करने से जुड़ी लागत काफी अधिक है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि क्षमता उपयोग विगत वर्षों के स्तरों से नीचे जा रहा है और विचाराधीन उत्पाद की मांग में किसी गिरावट के बिना 95 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक नीचे रहा है, जो आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए एक स्पष्ट कीममत वरीयता है।

इसके अलावा, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि भारतीय मांग में वृद्धि की आशा करते हुए आवेदकों ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया था। वास्तव में एस टी एल अपनी \*\*\* केएफकेएम की नई क्षमता (जो ऊपर सारणी में शामिल नहीं की गई) को चालू करने में विलंब करने पर मजबूर था क्योंकि घरेलू बाजार में मांग का अभाव था। तथापि, यह क्षमता अब चालू कर दी गई है और अगस्त, 2019 से उपयोग के लिए तैयार है, जिससे अगस्त, 2019 के बाद से क्षमता उपयोग और भी कम हो रहा है।

**ड. रोजगार**

आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान रोजगार के स्तरों में कोई पर्याप्त बदलाव नहीं आया है।

स्थान	2016-17	2017-18	2018-19	जन.-जून'19
एसटीएल बालुज (प्रवृत्ति)	100	110	110	107
एसटीएल शेन्द्रा (प्रवृत्ति)	100	201	167	153
बीएफएल (प्रवृत्ति)	100	112	112	110
घरेलू उद्योग का कुल रोजगार (प्रवृत्ति)	100	125	120	115

तथापि, बाजार अंश और क्षमता उपयोग में गिरावट को देखते हुए आवेदकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में (जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक) अपनी विनिर्माण क्षमता का एक हिस्सा बंद कर दिया है और अपने कुछ कार्यबल को निकालना पड़ा था :-

**च. उत्पादकता**

उत्पादकता में कमी के कारण हाल की अवधि में उत्पादकता में मामूली गिरावट आई है :-

उत्पादकता	2016-17	2017-18	2018-19	जन.-जून'19 (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग का उत्पादन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	114	120	103

रोजगार	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	125	120	115
उत्पादकता	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	90	99	89

### छ. लाभ/हानि

घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में विगत वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई है और वे हाल की अवधि में घाटे में चल रहे हैं। इतनी कम कीमतों पर आयात आने के कारण से घरेलू उद्योग पर्याप्त प्रतिफल/लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं है। लाभ/ हानि की प्रवृत्ति जैसा कि घरेलू उद्योग का दावा है, जांच की अवधि के दौरान इस प्रकार है :-

आंकड़े प्रवृत्ति में

	2016-17	2017-18	2018-19	जन.- जून' 19
घरेलू उद्योग की भारित औसत यूनिट बिक्री कीमत (गैर- कैप्टिव/गैर संबद्ध)	100	117	121	82
घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री लागत	100	103	112	118
घरेलू उद्योग का लाभ/ हानि	100	173	158	(65)

उपरोक्त से यह पता चलता है कि हाल की अवधि के दौरान आवेदक अपनी बिक्रियों की लागत से काफी कम कीमतों पर बिक्री करने पर मजबूर थे, जिससे भारी नुकसान हुआ। हाल की अवधि में विशेष रूप से 2019-20 की प्रथम तिमाही में बड़त ही कम कीमत पर आयात आने के कारण से आवेदक बिक्रियों की लागत में वृद्धि होने के बावजूद अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं थे और अपनी लागत से कम पर प्रस्ताव स्वीकार करने पर मजबूर हुए। घरेलू उद्योग द्वारा अंतिम चार तिमाहियों के लिए प्रस्तुत की गई लाभप्रदता का तिमाही वार विश्लेषण इस प्रकार है :-

लाभ/हानि	18-19 की दूसरी तिमाही	वित्त वर्ष 18-19 की तीसरी तिमाही	वित्त वर्ष 18-19 की चौथी तिमाही	वित्त वर्ष 19-20 की प्रथम तिमाही
एस टी एल (प्रवृत्ति)	100	99	11	(60)
वी एफ एल (प्रवृत्ति)	100	(36)	(144)	(200)

### ज. कम कीमत पर बिक्री, कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास

कम कीमत पर बिक्री, कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण नीचे सारणी में दिया गया है :

आंकड़े रूपए/एफकेएम में

प्रति यूनिट	जन-जून 2019
घरेलू उद्योग – भारित औसत युनिट बिक्री कीमत (एस पी)	***
भारित औसत उचित बिक्री कीमत (एफ एस पी)	***
पहुंच मूल्य (रू./ के एफ के एम) (एल वी)	411
कीमत कटौती (एस पी-एल वी)	(***)
कम कीमत पर बिक्री (एफ एस पी-एल वी)	***
कीमत ह्रास	***

हाल ही की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत के स्तर से काफी नीचे है। यह दर्शाता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है, जिससे घरेलू बाजार में उन्हें जारी रखना अव्यवहार्य हो गया।

नकारात्मक कीमत कटौती के मुद्दे पर घरेलू उद्योग ने ह कहा है कि उनके पास विश्वसनीय बाजार सूचना है कि निर्यातकों आयातकों को लंबी अवधि का ऋण अथवा भारी मात्रा में छूट प्रदान कर रहे हैं। इसकी प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों और आयातकों से प्राप्त उत्तरों के अनुसार जांच की जाएगी। प्राधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग \*\*\* प्रति एफकेएम की उचित बिक्री कीमत की तुलना में \*\*\* रु. प्रति एफकेएम बिक्री कीमत प्राप्त कर रहा है और ऐसी बिक्री कीमत विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और उचित बिक्री कीमत से कम है। अतः कीमत कटौती भारी कीमत दबाव के कारण कुछ नकारात्मक है तथापि, प्रारंभिक क्षति विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में उल्लिखित आयात कीमतों पर विचार किया गया है।

## झ. वस्तु सूची

नीचे दी गई सारणी वस्तु सूची के स्तर को दर्शाती है, जो जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि की साक्षी है।

आंकड़े प्रवृत्ति में

वित्तीय वर्ष/तिमाही	वस्तु सूची (एसटीएल)	वस्तु सूची (बीएफएल)	कुल घरेलू उद्योग
<b>2016-17</b>	100	100	100
<b>2017-18</b>	79	67	73
<b>2018-19</b>	567	171	356
<b>जन'19 से जून'19</b>	588	193	377

आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि वे अनुमानित बिक्रियों के अनुसार उत्पादन बना कर रखते हैं ताकि उच्च वस्तुसूची के रखरखाव से जुड़ी लागत से बचा जा सके। इसके परिणामस्वरूप उसके पास सामान्यतः सीमित स्टॉक उपलब्ध होगा। तथापि, आयातों के घातक प्रहार के कारण आवेदकों के कई ग्राहकों ने अपने अनुबंधों को मानने से इंकार कर दिया है जिससे अत्यधिक मात्रा में वस्तुसूचियां हो गई। इसके अलावा उत्पादन में कमी के कारण बीएफएल के पास भारी कच्ची सामग्री (पूर्व निर्मित) की वस्तुसूची बढ़ गई।

## 8. गंभीर क्षति का की आशंका

8.1 आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि उनके समक्ष आ रही गंभीर क्षति की समस्या के अलावा, हाल की अवधि और जांच की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि भारतीय घरेलू उद्योग के समक्षी भी गंभीर क्षति की आशंका आ रही है।

8.2 रक्षोपाय उपाय टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जी ए टी टी) के अनुच्छेद \*\*\* के तहत शासित हैं, जिसके तहत उद्योगों के संरक्षण के लिए रक्षोपाय उपाय करने की अनुमति है जो आयातों की "बढ़ती मात्रा" के कारण गंभीर क्षति अथवा ऐसी गंभीर क्षति की आशंका प्रदर्शित करता है। उसके अनुरूप सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख, उप धारा (i) में भी ऐसी वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए प्रावधान है, जो इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी स्थिति में भारत में आयात की जा रही है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने अथवा गंभीर क्षति होने की आशंका है। अतः जी ए टी टी और नगरपालिका कानूनों, दोनों के तहत यहां तक कि ऐसे मामलों में भी एक रक्षोपाय का उपाय किया जा सकता है, जहां घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की अत्यधिक आशंका है।

8.3 गंभीर क्षति की आशंका को एक ऐसी आशंका के रूप में समझा गया है जो तथ्यों के आकार पर स्पष्ट रूप से सन्निकट न हो न कि मात्र आरोपों, अनुमानों अथवा दूरस्थ संभावना पर आधारित हो। क्षति की आशंका का दावा एक निवारक व्यवस्था है जिससे जांच प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर वास्तविक गंभीर क्षति का प्रकाशन पड़ने से पूर्व कार्रवाई करते हैं।

- 8.4 रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1 (ख) के तहत, “गंभीर क्षति की आशंका” को ऐसी गंभीर क्षति से समझा जाएगा, जो पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से सन्निकट हैं। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि गंभीर क्षति की निकटस्थ क्षति की आशंका जांच की अवधि के लिए और हाल की अवधि के लिए अर्थात् जनवरी से जून की अवधि के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करने से स्पष्ट है। घरेलू उद्योग ने दिनांक 3.10.2019 के पत्र के तहत वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो उनकी स्थिति में और अधिक गिरावट को दर्शाते हैं।
- 8.5 आंकड़ों के विश्लेषण से, यह नोट किया जाता है कि आयातों में वर्ष 2016-17 में 1903 के एफ के एम से वर्ष 2018-19 में 7066 के एफ के एम की बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और यह अप्रैल, 2019 से जून, 2019 में वृद्धि के स्तर पर (6534 के एफ के एम, वार्षिक) जारी रहे। यह देखा गया है कि यद्यपि, हाल की अवधि में (वार्षिक) आयातों में बहुत ही मामूली गिरावट आई है लेकिन उनकी अत्यधिक कम कीमतों अर्थात् वर्ष 2018-19 में 603/एफ के एम की तुलना में 375/एफ के एम के कारण से उन पर घरेलू उद्योग को अधिक क्षति होने के बावजूद प्रभाव पड़ा है। आयातों और उनकी घटती कीमतों में निरंतर तेजी के बावजूद घरेलू उद्योगों की घरेलू बिक्रियों और बाजार अंश पर प्रभाव पड़ा है, जिससे हाल की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट आई है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि उनकी बिक्रियों में उनकी कीमतों में पर्याप्त कटौती के बावजूद गिरावट आई है। वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में यह स्थिति बहुत ही खराब रही और ग्राहक अब 270-280 रु. प्रति एफकेएम से कम कीमतों पर मोलभाव कर रहे हैं जो कि उत्पादन की लागत से काफी कम है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी हाल की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है और इसमें 2019-20 की दूसरी तिमाही में आगे और गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, अब कम कीमत के आयातों के प्रभाव से विनिर्माण डाउनस्ट्रीम उत्पादन अर्थात् केवल के लिए घरेलू उद्योग की कैप्टिव बिक्रियों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

8.6 यूएस – लाम्ब में पैनल ने गंभीर क्षति की आशंका के रूप में यूएसआईटीसी के विश्लेषण को त्रुटिपूर्ण माना है क्योंकि यह “प्रत्याशित” नहीं था और यह ऐसे अनुमानों की बजाए पूर्व के आंकड़ों पर आधारित था कि कैसे उद्योग को तत्काल भविष्य में निष्पादन करना था। उसमें पैनल ने कुछ अनुमान लगाए कि कैसे आशंका का विश्लेषण करें, जो इस प्रकार है :-

*“किसी आशंका का निर्धारण कुछ समय पूर्व के उद्देश्यपरक और सत्यापन योग्य आंकड़ों पर आधारित होना आवश्यक है। इस कुछ समय पूर्व के तथ्यों पर उद्योग की स्थिति में विकास के संबंध में और निकट भविष्य में आयातों के संबंध तथा आधारित अनुमानों के द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है और अंत में विश्लेषण में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या गंभीर मात्रा में क्षति वास्तव में रक्षोपाय कार्रवाई करने तक निकट भविष्य में उत्पन्न होगी।”*

8.7 आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि अभी हाल ही की अवधि के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि भारतीय घरेलू उद्योग पहले से ही गंभीर क्षति का सामना कर रहा है। आवेदकों की लाभप्रदता पूरी तरह से नष्ट हो गई है और आयात ऐसी अलाभकारी कीमतों/शर्तों पर आ रहे हैं कि भारतीय उद्योग आयातों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। वर्तमान प्रवृत्ति घरेलू उद्योग को आगे क्षति की अत्यधिक आशंका का एक स्पष्ट संकेत है। बाजार की प्रवृत्तियों के अपने दावे के समर्थन में, आवेदकों ने सी आर यू (मई, 2019 की रिपोर्ट) द्वारा किए गए घरेलू स्थिति के विश्लेषण और अनुमान पर भरोसा किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था :-

*“चीन में कीमतें ढेर होकर विदेशी बाजारों में धड़ाम से गिरीं”*

चीन में कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आने के साथ ही घरेलू निर्यात वर्तमान उत्पादन स्तर में सहायता और मौजूदा संयंत्रों में अधिक उपयोग करने के लिए निर्यात के अवसर तलाश रहे हैं। चीन के खुले फाइबर और केवल दोनों के निर्यातों में विगत कुछ माह के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। वास्तव में, निर्यात के लिए सी आर यू के अनुमान में एक मूल्य आधार पर वर्ष 2019 की प्रथम तिमाही में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 110 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जैसा कि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है, चीन के खुले फाइबर के यूरोप में निर्यातों में प्रथम तिमाही में 149 प्रतिशत कार्मिक की वृद्धि हुई है। इसी बीच भारत में निर्यातों में पांच गुणा वृद्धि हुई है। सी आर यू का मानना है कि इस सामग्री में अधिकांश कमजोर घरेलू कीमत के अनुसार अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर पेश की जा रही है और इससे दोनों ही लक्ष्य बाजारों में कीमतों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए सीआरयू ने भारत और मैक्सिको के लिए 4.50 डॉलर/एफ के एम अथवा कम प्रस्ताव के बारे में सुना है। चीन के निर्यातकों द्वारा निकट समय में इस बड़े हुए स्तर पर रहने की संभावना है। सीआरयू को आशा है कि पूरे वर्ष भर वैश्विक कीमतों पर निरंतर दबाव रहेगा।

8.8. सी आर यू द्वारा हाल ही के आंकड़ों के आधार पर अर्थात् वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही (जनवरी, 2019 से मार्च, 2019) में किए गए विश्लेषण और अनुमानों से यह स्पष्ट है कि भारतीय घरेलू उद्योग के समक्ष अत्यंत गंभीर क्षति की आशंका है। कथित रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन के बाजार में मंदी के साथ ही, चीन से भारत में आयातों में 5 गुणा वृद्धि हुई है और यह निम्न कीमतों पर आ रहे हैं। इसके अलावा, चीन के बाजार में मंदी ने वैश्विक रूप से फाइबर उद्योग पर दबाव डाला है।

8.9 हाल की अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही के आंकड़े आवेदकों की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त गिरावट को दर्शाते हैं। आयातों में न्यून पहुंच लागत पर तेजी ने घरेलू उद्योग का स्थान ले लिया है। इसके अलावा, चीन के बाजार में मंदी के कारण आप्टिकल फाइबर की वैश्विक क्षमता को अत्यधिक कर दिया है जिससे अन्य देशों में भी निर्यातकों को बाध्य कर दिया है कि वे गैर- चीन निर्यात बाजारों को देखें। इस प्रकार, प्रारंभिक विश्लेषण से वर्तमान परिस्थितियों में गंभीर क्षति की आशंका अत्यधिक है, जिसमें कि भारतीय उद्योग तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक कि उन्हें पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान न किया जाए ताकि वे आयातों से मुकाबला कर सकें।

## 9. नाजुक परिस्थितियां

9.1 आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि हाल की अवधि अर्थात् जनवरी, 19 से जून, 19 तक के दौरान आ रही गंभीर क्षति की समस्या के अलावा, घरेलू उद्योग की स्थिति वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में (जुलाई- सितंबर, 2019) में और भी खराब हो गई है। एस टी एल का क्षमता उपयोग 2018-19 की दूसरी तिमाही में \*\*\* से काफी घटकर 2019-20 की दूसरी तिमाही में \*\*\* हो गई है। बी एफ एल का क्षमता उपयोग वर्ष 2018 की दूसरी तिमाही (जुलाई- सितंबर) में \*\*\* की तुलना में वर्ष 2019 में जुलाई-अगस्त में काफी घटकर \*\*\* हो गया है। इसके अलावा, आवेदकों की वस्तु सूची भी उत्पादन में काफी गिरावट के बावजूद काफी अधिक स्तर पर आ गई है।

9.2 आवेदकों का यह भी कहना है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में हाल ही की अवधि में और साथ ही 2019-20 की दूसरी तिमाही में काफी गिरावट आई है। एस टी एल के विचाराधीन उत्पाद की औसत बिक्री कीमत में भी 2018-19 की दूसरी तिमाही में \*\*\* रु. प्रति एफकेएम से काफी गिरावट आकर 2019-20 की दूसरी तिमाही में \*\*\* रु. प्रति एफकेएम आ गई है। बी एफ एल के मामले में विचाराधीन उत्पाद की औसत बिक्री कीमत 2018-19 की दूसरी तिमाही में \*\*\* रु. प्रति एफ के एम से काफी गिरकर जुलाई 2019-अगस्त, 2019 में \*\*\* रु. प्रति एफकेएम तक आ गई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की हानि में जुलाई-अगस्त, 2019 में और भी गिरावट आई है और दोनों ही आवेदकों की स्थिति दूसरी तिमाही में और भी नाजुक हो गई। आवेदकों द्वारा यह भी बताया गया है कि व्यवहार्य बने रहने के लिए दोनों घरेलू उत्पादकों को 2019-20 की दूसरी तिमाही में अपने कार्यबल का एक हिस्सा बंद करने पर मजबूर होना पड़ा।

9.3 आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि आयात कीमतों में जुलाई-अगस्त, 2019 में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2018-19 के दौरान 603/एफ के एम की औसत सी आई एफ कीमत और जनवरी से जून, 2019 के दौरान 375 रु. प्रति एफ के एम की तुलना में आवेदकों ने 2019-20 की दूसरी तिमाही में कुछ आयात सौदों का उल्लेख किया है जहां पर आयात कीमतें यहां तक कि 280 रु./एफ के एम के स्तर से भी नीचे हैं।

9.4. आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि वर्तमान बाजार स्थिति को देखते हुए एस टी एल ने वर्तमान में अपने वालुज संयंत्र में अधिकांश टावरों से उत्पादन बंद कर दिया है। अगस्त, 2019 में शेन्ड्रा में चालू की गई क्षमता भी बहुत ही कम क्षमता उपयोग पर चल रही है। यहां तक कि बीएफएल ने व्यावहारिक रूप से उत्पादन बंद कर दिया है, लेकिन इसके क्षमता उपयोग से यह स्पष्ट है कि इसमें जुलाई-अगस्त, 2019 में काफी गिरावट आई है।

9.5 प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग कम कीमत के बढ़ते आयातों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों तथा औसतन बिक्री कीमतों में काफी गिरावट आई है। घरेलू बाजार में आदेशों की कमी के कारण घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग का अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर पाया है, जो कि शेष व्यवहार्यता के लिए आवश्यक है। अतः आयातों की वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की आशंका है और घरेलू उद्योग की स्थिति बहुत ही नाजुक है, जहां अनतिम रक्षापाय उपाय के रूप में तत्काल संरक्षण प्रदान करने में विलंब है।

## 10. आयातों में वृद्धि और गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की आशंका के बीच कारणात्मक संबंध ।

10.1 कोरिया – डेयरी के संबंध में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने “कारणात्मक संबंध” के निर्धारण के लिए बुनियादरी संकल्पना स्थापित की है, जो इस प्रकार है :-

“इसके कारणात्मक संबंध का आकलन करने में हमारा यह विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने और निर्धारित करने की जरूरत है कि क्या उद्योग में विकास पर राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा गंभीर क्षति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विचार किया गया, वह आयातों में वृद्धि के कारण से है । इसके कारणात्मक आकलन में, राष्ट्रीय प्राधिकारी को एक उद्देश्यपरक और मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करना जरूरी है, जिनका उस उद्योग की स्थिति से संबंध है । इसके अलावा, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी के पास आयातों में वृद्धि के अलावा, अभिज्ञात कारक भी है, जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कारकों के कारण कोई क्षति आयातों में वृद्धि होने के कारण से हुई नहीं मानी जाए । एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए, कोरिया को यह प्रदर्शित करना है कि उसके घरेलू उद्योग को क्षति आयातों में वृद्धि के कारण से है । दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना है कि उसके एसएमपीपी के आयातों को दुग्ध पाउडर और कच्चा दुग्ध उत्पाद करने वाले घरेलू उद्योगों के कारण क्षति हुई है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद कोरियाई प्राधिकारी का यह दायित्व है कि आयातों में वृद्धि अन्य कारकों के कारण हुई किसी क्षति के कारण न हो । ”

10.2 वर्ष 2016-17 से 2018-19 तथा जनवरी-जून, 2019 तक की अवधि के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात महत्वपूर्ण उच्च स्तर पर रहे हैं और साथ ही विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें भी हाल की अवधि में अत्यधिक नीचे आई हैं । इसके कारण घरेलू उद्योग को हाल की अवधि में अपनी कीमतें कम करते हुए संशोधित करनी पड़ी जिनके चलते हानि हुई । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में विगत तिमाही और आधार वर्ष तथा विगत वर्ष की तुलना में तेजी से गिरावट आई है ।

10.3 इन परिस्थितियों के तहत और उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह प्रारंभित तौर पर निष्कर्ष दिया गया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति (और तत्संबंधी आशंका) तथा आयातों में अचानक से आई तेजी के बीच स्पष्ट और प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध है । घरेलू उद्योग के बाजार अंश में गिरावट की अवधि, बिक्रियां (मात्रा और कीमत), क्षमता उपयोग तथा लाभप्रदता आदि का उस अवधि से सीधा संबंध है जब आयातों में अचानक और महत्वपूर्ण तेजी आई थी । आयातित उत्पाद से घरेलू उद्योग के बाजार को पूरी तरह पाटा गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और आगे क्षति की आशंका है । अतः उपरोक्त मापदंडों का एक व्यापक मूल्यांकन यह प्रदर्शित करता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और यह महत्वपूर्ण वृद्धि भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है और विचाराधीन उत्पाद के निरंतर बढ़ते अत्यधिक कम कीमत के आयातों के कारण जारी रहने की संभावना है । एक उद्देश्यपरक और मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों का घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के कारणात्मक संबंध के निर्धारण से संबंध है जिसका प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया है ।

## 11. समायोजन योजना

11.1 आवेदक ने एक विस्तृत समायोजन योजना प्रस्तुत की है, जिससे उन्हें कच्ची सामग्री के बेहतर उपयोग, कच्ची सामग्री की खरीद लागत में कटौती और उत्पादन प्रक्रिया में बाधाओं (यदि कोई हो) को दूर करके अर्थक्षम किफायतता हासिल करने में मदद मिलेगी।

11.2 प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों ने एक व्यवहार्य समायोजन योजना प्रस्तुत की है, जिसकी जांच की शेष अवधि के दौरान जांच की जाएगी ।

## 12. लोक हित

12.1 यह विश्लेषण करने की अपेक्षा कि क्या रक्षोपाय उपाय लागू करना लोक हित में होगा, रक्षापाय करार की धारा 3.1 के तहत है, जिसमें यह कहा गया है :-

“कोई सदस्य पहले स्थापित प्रक्रिया और जी ए टी टी, 1994 के अनुच्छेद x के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी जांच का अनुपालन करने के बाद ही रक्षोपाय उपाय लागू कर सकता है । इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को तर्कसंगत सार्वजनिक सूचना और सार्वजनिक सुनवाई अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम शामिल हैं जिनमें कि उत्पादक, निर्यातक और अन्य दिहतबद्ध पक्षकार साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें और अपने विचार प्रकट कर सकें, जिसमें अन्य पक्षकारों को प्रस्तुति करने और अन्य के साथ अपने विचार प्रकट करने के लिए

अवसर प्राप्त हो सके कि क्या एक रक्षोपाय उपाय लागू करना लोकहित में होगा अथवा नहीं। सक्षम प्राधिकारी उनकी जांच के निष्कर्षों और सभी संबंधित तथ्यात्मक और कानून मामलों तक पहुंचने के लिए तर्कसंगत निष्कर्षों की स्थापना के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।”

- 12.2 यद्यपि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख और सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के तहत लोक हित में एक जांच अपेक्षित नहीं है। इस लोक हित का रक्षोपाय करार अनुच्छेद 3.1 के तहत निश्चित रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश करने से पूर्व निरंतर मूल्यांकन किया गया है। इसका हितबद्ध पक्षकारों से उत्तर प्राप्त होने और उसकी जांच होने के बाद शेष जांच के दौरान मूल्यांकन किया जाएगा।

### 13. प्रारंभिक जांच परिणाम

- 13.1 सारांश यह है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यकरण में समग्र गिरावट आई थी। इसके अलावा, गिरावट के मापदंडों की प्रवृत्ति गंभीर क्षति और भविष्य में गंभीर क्षति की आशंका जारी रहने की संकेतात्मक है। घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति के मापदंड-वार निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

- (क) विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है और ये सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों तरह से वृद्धि के स्तर पर जारी हैं।
- (ख) घरेलू उद्योग के बाजार अंश में गिरावट आई है जबकि आयातों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार अंश का स्थान ले लिया है।
- (घ) क्षमता उपयोग में मांग में वृद्धि के बावजूद महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- (ङ.) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में हाल की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है और उनका बाजार अंश पूरी तरह से आयातों के कब्जे में है।
- (च) अब घरेलू उद्योग ने अपनी निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा बंद कर दिया है और अब बहुत ही कम क्षमता उपयोग पर चल रहा है।
- (छ) घरेलू उद्योग वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में अपने कार्यबल को हटाने पर मजबूर हुआ।
- (ज) घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।
- (झ) जो घरेलू उद्योग वर्ष 2017-18 में लाभ अर्जित कर रहे थे वे अब अत्यधिक हानि का सामना कर रहे हैं।
- (ञ) विचाराधीन उत्पाद की वस्तु सूची में घरेलू उद्योग के भीतर काफी वृद्धि हुई है; और
- (ट) विचाराधीन आयातित उत्पाद में पाटन काफी कम कीमत पर बिक्री और कीमत में दबाव आ रहा है।

- 13.2 यह नोट करना संगत है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति जारी रही और वह आगे भी गंभीर क्षति की आशंका का सामना कर रहा है। आयात की मात्रा की प्रवृत्ति यह सुझाती है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात भविष्य में जारी रहने की संभावना है। इस प्रकार से गंभीर क्षति की निकटस्थ क्षति भी इस मामले में पाई गई है।

- 13.3 उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए यह नोट किया गया था कि घरेलू उद्योग के समक्ष पहले आई गंभीर क्षति और आयातों में वृद्धि के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है। स्पष्ट है कि सभी संकेत ऐसे जांच परिणाम के लिए मौजूद हैं जिनसे आयातों में वृद्धि हुई, जो वृद्धि के स्तर पर गिरावट की कीमत पर जारी हैं। जिनसे आने वाले दिनों में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की आशंका हो रही है। इस प्रकार ऐसी नाजुक परिस्थितियां मौजूद हैं, जिनमें तत्काल अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने की आवश्यकता है ताकि घरेलू उद्योग को आगे गंभीर क्षति से बचाया जा सके, जिसे ठीक करना कठिन होगा, यदि इस रक्षोपाय उपाय को लागू करने में विलंब होता है। वास्तव में दर्ज दस्तावेजों और सूचना के आधार पर ऐसे प्रारंभिक जांच परिणाम हैं और यदि जांच की अवधि के दौरान ऐसे कारक सामने आते हैं जिनका इनसे सीधा संबंध है, तो उनकी यथा समय विस्तार से जांच की जाएगी।

#### (च) विकासशील राष्ट्र

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 (ख)(1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क एक विकासशील देश के मूल की वस्तुओं पर तब तक नहीं लगाए जाएंगे, जब तक कि उसका आयातों का अंश उस वस्तु के कुल आयातों का 3 प्रतिशत से अधिक न हो जाए अथवा जहां वह वस्तु एक से अधिक विकासशील देशों के मूल की



हो, तब ऐसे सभी विकासशील देशों से समग्र आयात, प्रत्येक का 3 प्रतिशत आयात अंश, मिलकर उस वस्तु के कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक न हो जाए। इसके अलावा, दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एन टी) के तहत इस प्रावधान के प्रयोजन से विकासशील देशों को विनिर्दिष्ट किया गया है। कथित अधिसूचना के साथ पठित इस कानूनी प्रावधान को वर्तमान मामले में उपलब्ध आंकड़ों के साथ लागू करके जांच परिणाम यह है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य सहित एक से अधिक विकासशील देशों के मूल से है। तथापि, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के रूप में चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से अलग-अलग आयात 3 प्रतिशत से अधिक होता है जबकि प्रत्येक अन्य विकासशील देश का अंश अलग-अलग 3 प्रतिशत से कम है। साथ ही, विकासशील देशों का साझा हिस्सा जिनका अलग-अलग अंश 3 प्रतिशत से कम है, भारत में विचाराधीन के कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए यह माना जाए कि विकासशील देशों (चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य को छोड़कर) के मूल के विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (1) के परंतुक के संदर्भ में रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

#### (छ) सिफारिशें

14. उपरोक्त विश्लेषणों और जांच परिणामों को देखते हुए प्राधिकारी प्रारंभिक रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अर्थात् "सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर" का भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी स्थितियों में आयात हो रहा है जिससे कि समान और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादों के निर्माता घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका है। प्राधिकारी यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि मौजूदा नाजुक परिस्थितियां तत्काल अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने को न्यायोचित ठहराती हैं, ताकि घरेलू उद्योग को आगे गंभीर क्षति होने से बचाया जा सके, जिसे ठीक करना कठिन होगा, यदि अनंतिम रक्षोपाय उपाय लागू करने में विलंब होता है। तदनुसार, प्राधिकारी निम्नलिखित सिफारिश करते हैं :-

- i. एक अनंतिम निर्धारण के लंबित रहते, घरेलू उद्योग की भारित औसत उचित विक्री कीमत पर विचार करते हुए, जो लागत और उस पर तर्कसंगत प्रतिफल और वर्तमान औसत आयात कीमत के आधार पर है, एक अनंतिम रक्षोपाय 25 प्रतिशत की दर पर लगाने का प्रस्ताव है, जो नीचे खंड (iii) में उल्लिखित विकासशील देशों को छोड़कर सभी देशों से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की सीमाशुल्क टैरिफ मद 9001 10 00 के तहत आने वाले विचाराधीन उत्पाद अर्थात् "सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर" के आयातों पर सी आई एफ कीमत पर मूल्यानुसार है। यहां उल्लिखित टैरिफ केवल संकेतात्मक है और आयातित वस्तुओं का विवरण अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगा।
- ii. उपरोक्त कथित उत्पाद के आयात पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क 200 दिनों (दो सौ दिनों) की अवधि के लिए लगाया जाएगा।
- iii. चूंकि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य को छोड़कर दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एन टी) में सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयात अलग-अलग 3 प्रतिशत से अधिक और समेकित रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अतः ऐसे विकासशील देशों (चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य को छोड़कर) के मूल के "सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर" के आयातों से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (1) के प्रथम परंतुक के संदर्भ में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।

#### ज. आगे की प्रक्रिया

15. प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- i. महानिदेशक प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं। उनसे प्राप्त टिप्पणियों की अंतिम जांच परिणाम में जांच की जाएगी।
- ii. महानिदेशक सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच के लिए संगत अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर देने के लिए मौखिक सुनवाई करेंगे। मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए प्रश्नों और चिंताओं की अंतिम जांच परिणाम में जांच की जाएगी।
- iii. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर अलग से घोषित की जाएगी।
- iv. महानिदेशक यथा आवश्यक सत्यापन करेंगे।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2019

**Case No. (SG) 05/2019**

**Subject : Safeguard investigation concerning imports of “Single Mode Optical fibre” in to India - Preliminary Findings – Proceedings under Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (identification and Assessment of Safeguard) Rules, 1997- Reg.**

**Reference F. No. 22/5/2019-DGTR.—****A. Introduction**

1. An application dated 18.07.2019 has been filed before the Director General (Safeguard) under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred to as the “said Rules”) by M/s Sterlite Technologies Limited (‘STL’) and M/s Birla Furukawa Fibre Optics Private Limited (‘BFL’) (hereinafter also referred to as the “Applicants”) in terms of Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 (for brevity, “the Act”) read with Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (for brevity, “the Rules”), through M/s TLC Legal, Advocates, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Single Mode Optical Fibre” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC”) into India to safeguard the Domestic Industry of like or, directly competitive products from serious injury or threat of serious injury caused by increased imports. The applicants have submitted that imports of subject goods has increased significantly in 2018-19 and has continued to be at increased levels in the most recent period, i.e. January’ 19 to June’ 19. The applicants have claimed that they are not able to compete with the imports and regain their market share, thereby forcing them to close down or keep part of their production facilities idle. For this reason, the applicants have also requested for imposition of provisional Safeguard Duty as an urgent measure to mitigate their injury.

**B. Procedure Followed**

2. An examination of the application and the evidence / details / documents submitted therewith led to the conclusion that the application satisfies the requirements of Rule 5 of the said Rules. Therefore, a Safeguard investigation against imports of the PUC into India was initiated vide Notice of Initiation (NOI) dated 23.09.2019. The NOI was published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23.09.2019 vide GSR No.293 (E).

3. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the NOI dated 23.09.2019 and a copy of a Non-confidential Version (NCV) of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry and Ministry of Finance, the Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application. Further, the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules, was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the NOI.

**C. Observations**

4. The Director General has carefully examined the said application and the duly certified financial and other records produced by the applicants. The preliminary observations of the Director General on various factors that are relevant to the present investigation for imposition of a Safeguard Duty on imports of “Single Mode Optical Fibre” into India to protect the Domestic Industry of like and directly competitive products against serious injury / threat of serious injury caused by their increased imports are as follows:

**4.1 The Product Under Consideration (PUC)**

4.1.1 The product concerned is “Single-mode Optical Fibre” (“SMOF”). SMOF refers to the Optical Fibre which facilitates transmission of a single spatial mode of light as a carrier and is used for signal transmissions

within certain bands. The standardized single mode optical Fibre types include the Non-dispersion shifted Fibre (G.652), Dispersion shifted Fibre (G.653), Cut-off shifted single mode optical Fibre (G.654), and Non Zero Dispersion Shifted Fibres (G.655 & G.656) as well as Bend insensitive single mode Fibre (G.657) - as defined by International Telecommunication Union (ITU-T), which is a global standardization body for telecommunication systems and vendors.

4.1.2 Single-mode Optical Fibre is used for manufacture of Optical Fibre Cables, including Uni-tube and Multi tube stranded cables, tight buffer cables, Armoured and Un-armoured cables, ADSS & Fig-8 cables, Ribbon cables, Wet core and Dry core cables and etc. Single-mode Optical Fibre is mainly applied to high-data rate, long distance and access network transportation, therefore, is mainly used in long-haul, metro area network, CATV, optical access network (for example FTTH) and even over short distance networks as applicable. Major consumption is driven by 3G/4G/5G rollout by Telco's, Connectivity of Gram Panchayat, Defence (NFS Project) and Data centres.

4.1.3 The product concerned is Single Mode Optical Fibre, which are classifiable under Customs Tariff heading 9001 10 00 of the Second Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification be taken as indicative only, and is not binding on the scope of the product.

## 4.2 Domestic Industry (DI)

4.2.1 Clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines Domestic Industry (hereinafter also referred to as the "DI"), as follows:

'(b) "Domestic industry" means the producers –

- i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
- ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.'

The applicants have claimed that their collective production accounts for more than 50% of the total production of the PUC in India represent a major share of the total Indian production of the PUC. The applicants may be treated as the Domestic Industry.

KFKM	2016-17	2017-18	2018-19	Jan to June 2019	Jan to June 2019 (Annul.)
<b>Total Indian Production</b>	42612	47861	50590	22428	44856
<b>Trend</b>	100	112	118	105	105
<b>DI Production as % of Total Production</b>	***	***	***	***	***

4.2.2 The applicants have also claimed that they do not have access to production data of other Domestic manufacturers. However, all other domestic manufacturers produce PUC from imported preform (which cannot be used for any other known purpose). Accordingly, estimate of total industry production has been made by them adopting the standard industry norm that 37 FKM Fibre can be manufactured from 1 Kg of Preform with ~90% After-Draw-Yield. Thus, on an average, it has been assumed by the Applicants in their application that 1 Kg of Preform will yield 33.3 FKM of Fibre. Accordingly, the Applicants have computed the total Indian Production by applying the aforesaid conversion ratio to the Preform import data obtained from Cybex Exim Solutions Pvt. Ltd. ("CESPL", for brevity) after excluding Preform imports by the Applicants.

4.2.3 Subsequently, the Director General has received letter dated 30.09.2019 from M/s Finolex Cable Ltd. ('Finolex', for brevity), who is also a domestic producer of the PUC, supporting initiation of investigation and requesting for imposition of provisional duties. They have also submitted their production, capacity, sales and inventory information for 2016-17 to 2018-19 and April 2019 to September 2019.

4.2.4 The Authority in view of the above for the purpose of preliminary finding pending final determination holds that the production of the applicants constitutes a major share of the total production of the said products

in India, and are considered as Domestic Industry in terms of clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

#### 4.3 Period of Investigation (POI)

4.3.1 The Customs Tariff Act, 1975 and the said Rules as well as the Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT has not defined the period of investigation. However, it is evident that the investigation period should be adequately long and sufficiently recent in time to allow reasonable conclusions to be drawn on the basis of various relevant factors such as domestic market conditions, performance of DI etc., as to whether or not the increased imports are indeed causing serious injury or threatening to cause serious injury to the DI and therefore justify the need for imposition of Safeguard Duty. On this basis, in the facts of the present case, it is considered reasonable and just to determine the period of investigation (POI) as 2016-17 to 2018-19 and 2019-20 (upto June' 2019). Analysis of most recent period, i.e. January 2019 to June 2019 has been done to examine the extent of serious injury, threat of serious injury and existence of critical circumstances.

#### 4.4 Source of Information

4.4.1 Initially the data in the Application was submitted for the period 2015-16 to 2018-19 and April 2019 to May 2019. Subsequently, it was updated to include data till June 2019.

4.4.2 The DI have submitted transaction-wise import data for the PUC, which has been sourced from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce, Government of India for the period from 2016-17 to 2018-19. For the first quarter of 2019-20, the DI had initially submitted transaction wise import data from a secondary source. However, subsequently the Director General has obtained data for first quarter of 2019-20 from DGCI&S which has been considered for analysis.

4.4.3 The corresponding data relating to injury parameters for the period 2016-17 to 2018-19 and 2019-20 (upto June, 2019) in respect of the DI itself has been submitted by the applicants. All these data has been taken into consideration for analysis.

#### 4.5 Confidentiality of Information Submitted

4.5.1 The DI has provided some information in their application on confidential basis and has requested that it be treated as confidential. The DI has also provided a non-confidential version (NCV) of their application, as required under Rule 7 of the said Rules read with Trade Notice dated 21.12.2009 issued by Director General (Safeguards) under File No. D-22011/75/2009. Further, the DI has submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information.

4.5.2 In terms of Rule 7 of the said Rules, the applicant may choose not to disclose information which is by nature confidential and provide a non-confidential summary thereof. The DI have submitted reasons for claiming confidentiality of the information and furnished a non-confidential summary of the information filed on confidential basis. Since, the reasons satisfy the requirements of Rule 7 of the said Rules, the confidentiality claimed by the applicants is hereby granted.

### 5. Increasing Imports in Absolute Terms

5.1.1 The PUC is being imported into India from various countries including China PR, Japan, and Korea RP. The major quantity of the PUC is being imported from China PR. The applicants have claimed that there has been a sudden, sharp and significant increase in imports in 2018-19, which has continued to be at high levels even in the most recent period, January 2019 to June 2019. The import volumes of the PUC have increased from 1,903 KFKM in 2016-17 to 9,918 KFKM in 2018-19. M/s (STL) has also imported the subject goods from 2018-19 onwards. Therefore, for an accurate analysis of surge in imports and serious injury, the DI imports have been excluded from total imports and examination has been made considering only Non- DI imports and is tabulated below.

In KFKM	2016-17	2017-18	2018-19	Jan'19- June'19	Jan'19- June'19 (annl.)
<b>Imports Total</b>	1903	2469	9918	4,268	8,536
<b>Trend</b>	100	130	521	521	449
<b>Imports (non DI)</b>	1,903	2,469	7,066	3,267	6,534
<b>Trend</b>	100	130	371	371	343

5.1.2 The Imports (non DI) has increased from 1,903 KFKM in 2016-17 to 7066 KFKM in 2018-19, and have continued to be at increased levels in the most recent period (6,534 KFKM). There has been significant increase of 271% in 2018-19 from the base year 2016-17.

5.1.3 There has been a significant surge in each quarter of 2018-19 and Quarter 1 of 2019-20, compared to previous year(s), as indicated below. The applicants have submitted that in Quarter 2 of 2018-19 there was an unprecedented rise in imports, which completely disrupted the domestic market. The imports thereafter have decreased, nevertheless, they have continued to be at high levels, and has been on an increasing trend.

Imports (Non DI)KFKM	Quarter 1	Quarter 2	Quarter 3	Quarter 4
2017-18	769	545	540	615
2018-19	1244	2797	1436	1589
2019-20	1678			

## 5.2 Increasing Imports in Relative Terms

5.2.1 Relative to domestic production, imports of the PUC are found to have consistently increased between 2016-17 to 2018-19 and January- June' 2019 and has more than tripled from the base year as well as previous year level.

In KFKM	2016-17	2017-18	2018-19	Jan'19- June'19*	Jan'19- June'19 (annl.)
<b>Imports (non DI)</b>	1,903	2,469	7,066	3,267	6,534
<b>Trend</b>	100	130	371	343	343
<b>DI Production</b>	***	***	***	***	***
<b>Trend</b>	100	114	120	103	103
<b>Import as % trend of DI Production</b>	100	114	329	357	357

## 5.3 Unforeseen Developments

5.3.1 Neither Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 nor the Rules made there under impose an obligation on the Director General (Safeguards) to analyze the unforeseen developments as a result of which the increased imports have occurred. The legal provisions neither contain any parameters that must be verified to identify the unforeseen developments nor do they specify any methodology that must be followed in the analysis of such unforeseen developments. However, the Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine “unforeseen developments” that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the DI. In view of this requirement, the Director General has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. Therefore, even in the present case, it is considered appropriate to examine the unforeseen developments or circumstances that have led to the sharp increase in the imports of the PUC during the period of investigation. However, in order to do so, it is necessary to first appreciate the import of the term “unforeseen developments or circumstances” and for this, a reference needs to be made to various rulings of the Appellate Body of WTO.

5.3.2 The Appellate Body of WTO in **Argentina–Footwear (EC)**<sup>6</sup> case held that imports in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers, must have been ‘unexpected’. In that case it was also held that the development of increased imports must have been due to “unforeseen developments”. Similarly, the **Appellate Body of WTO in Korea–Dairy**<sup>7</sup> case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation. In that case it was also recognized that unforeseen developments are circumstances which must be demonstrated as a matter of fact. In another case, the Panel on **US-Steel Safeguards**<sup>8</sup> concluded that the

<sup>6</sup> Appellate Body Report, Argentina- Footwear (EC), para 90

<sup>7</sup> Appellate Body Report, Korea- Dairy, Para 85 and 89

<sup>8</sup>US – Steel Safeguards, para. 315

confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development. It was also noted that increased imports must be an outcome of unforeseen developments i.e., it is the unforeseen developments that resulted in increased imports.

5.3.3 Applying the aforementioned findings to the present case, it is clear that the temporal nature of the increase in imports of the PUC so as to cause serious injury to the DI or give rise to a threat of such serious injury must have been unforeseen or unexpected and factual. Whereas the event of increased imports itself must be demonstrable on the basis of data on imports, a finding on its unforeseen or unexpected nature must be contextual.

5.3.4 In the present investigation, the applicants have submitted that the sudden increase in imports in 2018-19 and the POI was a consequence of certain unforeseen developments in the global market. There is a confluence of a number of developments such as global over-capacity in Fibre industry, imposition/extension of trade measures by China against most of the Fibre manufacturing countries, policy restrictions imposed by countries like USA, Australia on import of telecom equipment/components from China and other non-fiscal/non-regulatory restrictions imposed by major telecom operators (especially telecom operators in western Europe and USA) against China made Fibre, has resulted in sudden diversion of imports to India. It has been submitted that the Chinese market, which is the biggest consumer and producer of Optical Fibre, is facing a slump caused by their over-capacity and lower domestic demand. Moreover, China made Optical Fibre is not approved by major Telecom operators in many western countries including USA and most of the Europe. Therefore, the Chinese manufacturers have a restricted international market and are forced to off-load their production in nearby growing markets.

5.3.5 Further, China has imposed anti-dumping duty against most of the Optical Fibre manufacturing countries including India, Japan and the USA. Consequently, Chinese market, which is the biggest consumer of the subject goods, has become unviable for exporters from other countries. These factors have forced exporters in China as well as other countries to look for other viable export options. India being a growing demand market, has become a soft target for the exporters to off-load their excess production.

5.3.6 From the data available on record, it is seen that there was a sudden diversion of imports to India from Quarter 1 and 2 of 2018-19. This coincides with the period when Chinese market had started facing over-supply issues, *inter alia* because of sudden increase in its Fibre manufacturing capacity, delay in tender of China Mobile, which is the biggest consumer of Optical Fibre in China as well as globally. Further, with the slump in Chinese market which consumes around 50% of global Optical Fibre production, foreign producers in other countries were also left with excess production.

5.3.7 Thus, the sudden and sharp increase in imports of the PUC during 2018-19 and the most recent period is an outcome of a combination of various global events, which were unforeseen or unexpected. This surge in imports has significantly modified the competitive relationship between the imported and domestically produced PUC to the disadvantage of the DI.

## 6. Legal Provisions for Preliminary determination of Safeguard Measure

6.1.1 The applicants had requested for imposition of Provisional Safeguard measures in their application. They have further brought forth evidences of Critical circumstance from the data of Quarter 2' 2019-20 (July – September, 2019) in addition to the POI, vide their letter dated 03.10.2019 and submitted that delay in imposition of provisional levy will cause irreparable damage to them.

6.1.2 Section 8B (2) of the Act, enables the Director General for recommending imposition of a provisional safeguard duty on the basis of a preliminary determination that increased imports have caused or threaten to cause serious injury to a domestic industry pending determination under Section 8B (1).

6.1.3 Article XIX of the GATT, 1994, describes Safeguard measures as “Emergency Action on imports of Particular Products”. This sense of urgency or emergency has been adopted in our Municipal Legislations as well. Rule 9 of the said Rules require the Director General to proceed expeditiously with the conduct of the investigations and in critical circumstances, to record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury. The relevant portion of the Rule is reproduced as under:

“(1) The Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he may record a preliminary findings regarding serious injury or threat of serious injury.”

6.1.4 The term “critical circumstances” has been defined in Rule 2(b) as under:

“Critical circumstances” means circumstances in which there is clear evidence that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry and delay in imposition of provisional safeguard duty would cause irreparable damage to the domestic industry”

6.1.5 The provisions in the Municipal law are in consonance with Article 6 of the Agreement on Safeguards under GATT 1994, which also provides that in critical circumstances where delay would cause damage, which it would be difficult to repair, a member may take a provisional safeguard measures pursuant to a preliminary determination that there is a clear evidence that increase in imports have caused or are threatening to cause serious injury. The Article 6 further provides that the Provisional safeguard measures can be imposed only for a period of 200 days, during which period the Director General has carry out analysis required under Article 2 through 7 (which *inter alia* deals with investigation/ determination of serious injury) and 12. Further, Article 6 as well as Rule 15 of the Safeguard Rules provides for refund of duty, if the duties imposed on the basis of concluded investigation is lower than the provisional duty already imposed.

6.1.6 From a harmonious reading of the Act and Rules under Municipal law and the provisions of Agreement on Safeguards under GATT, it follows that the law contemplates recording of interim measures expeditiously in appropriate cases. Accordingly, analysis of increased imports, serious injury or threat and critical circumstances warranting imposition of provisional levy has been done herein under, to examine whether the present case falls within the category of “critical circumstances” warranting imposition of Provisional levy.

## 7. Serious Injury:

7.1.1 From above, Preliminary Finding recommending imposition of safeguard measure is required to be given in cases where there is:

- i. Evidence of increased imports;
- ii. Such imports have caused or are threatening to cause serious injury;
- iii. Existence of critical circumstances, where delay would cause irreparable damage.

7.2 The aspect of increased imports has been dealt with in detail in foregoing paragraphs. The import data clearly suggest that there has been a sharp and significant increase in imports, both in absolute terms and relative to domestic production. The analysis of existence of serious injury/threat of serious injury and critical circumstances is made herein under.

7.3 The term “serious injury” has been defined in sub Section (6) of Section 8B of the Act, as an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry. “Threat of serious injury” has been defined therein as a clear and imminent danger of serious injury.

7.4 The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically require that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. In this regard, reference may be made to the decision of **Argentina – Footwear (EC)**<sup>9</sup>, wherein the Appellate Body discussed the relationship between the definition of “serious injury” in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of “all relevant factors” in Article 4.2(a):

*“[I]t is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is ‘a significant overall impairment’ in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the*

<sup>9</sup> Appellate Body Report, Argentina – Footwear (EC), para. 139.

particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is 'declining'. In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show 'significant overall impairment' in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of 'serious injury' in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of 'serious injury'.

**7.5** Further the Panel in **US – Wheat Gluten**<sup>10</sup>, in a finding which was upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term "serious injury":

*"[A] determination as to the existence of such 'significant overall impairment' can be made only on the basis of an evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.*

*[W]e do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made."*

**7.6** Accordingly, in analyzing serious injury, threat of serious injury and critical circumstances for consideration of imposition of provisional duty, factors which are mentioned in the rules and are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered, as discussed herein below:

**a. Changes in level of Sales:**

The Applicants' Domestic sales to independent customers have declined significantly as compared to the previous years.

(KFKM)	2016-17	2017-18	2018-19	Jan'19 to June'19	Jan'19 to June'19 (Annl.)
<b>Combined DI Domestic Sales (Non-captive/Non related)</b>	***	***	***	***	***
<b>Trend</b>	100	65	48	31	31
<b>Imports (Non DI)</b>	1,903	2,469	7,066	3,267	6,534
<b>Trend</b>	100	130	371	343	343

It follows from the above table that in 2016-17 the imports was 1903 KFKM and DI sales was \*\*\* KFKM. The situation has reversed in 2018-19 with imports increasing to 7066 KFKM and DI sales being reduced to \*\*\* KFKM. The share of market lost by DI has been substituted by the increased imports.

**b. Market Share of imports and domestic producers in domestic demand:**

The Applicants have submitted that they do not have access to sales data of other Indian producers, therefore, total Indian Consumption number has been taken from quarterly reports of CRU, a body which specialises in studying and analysing commodity markets, including Optical Fibre market. The DG for the purpose of Preliminary Finding has considered the CRU report for the purpose of referencing demand pending final determination.

<sup>10</sup>Panel Report, US – Wheat Gluten, paras. 8.80 and 8.85.



For the analysis of share in market for independent consumers, the consumption of PUC by the domestic industry (either by captive/related party sale or imports) has been excluded from the Total Indian consumption as reported in CRU and the percentage share in demand is tabulated below.

*Fig: In KFKM*

	2016-17	2017-18	2018-19	Jan'19- June'19	Jan'19- June'19 (Annl.)
<b>Indian Consumption as per CRU</b>	27062	32186	35197	17547	35094
<b>Indian Consumption for independent customers</b> (excluding DI's Captive/Related party sales and DI imports)	17,971	15,057	12,948	8,763	17526
<b>Imports (Non DI)</b>	1,903	2,469	7,066	3,267	2186
<b>DI Domestic Sales (Trend)</b>	100	65	48	31	31
<b>Imports (Non DI) share in demand for independent customers</b> (excluding DI's Captive/Related party sales and DI imports)	11%	16%	55%	37%	37%
<b>Trend of DI's Share in demand for independent customers</b> (excl. DI's Captive consumption and related party sales)	100	77	67	31	31

**c. Changes in level of Production:**

The production of the domestic industry in the most recent period has substantially declined in comparison to 2017-18 & 2018-19 though the demand has increased substantially.

<b>Production (KFKM)</b>	2016-17	2017-18	2018-19	Jan' 19- June 19	Jan' 19- June 19 (Annl.)
<b>STL (Trend)</b>	100	115	123	117	117
<b>BFL (Trend)</b>	100	111	109	62	62
<b>Total DI Production (Trend)</b>	100	114	120	103	103

**d. Capacity Utilisation:**

The capacity utilisation of the Domestic industry is given below.

<b>Capacity Utilization</b>	2016-17	2017-18	2018-19	Jan'19- June'19	Jan- June' 2019 (annualised)
DI Installed Capacity (KFKM)	100	112	135	143	143
DI Production (KFKM)	100	114	120	103	103
DI Capacity Utilization	100	103	89	73	73

The capacity utilisation of the Domestic industry has declined from \*\*\* in 2017-18 to \*\*\* in the most recent period.

The Applicants have claimed that the optimum capacity utilization for this industry is around 100%, as the cost associated with reducing production or restarting plant is very high. The DI has further claimed that the capacity utilization going below previous years' levels and remaining below 95% to 100% without there being any fall in demand of PUC, indicates a clear price preference for the imported PUC.

Moreover, the applicants have submitted that anticipating the increase in Indian demand, the applicants had made huge investments for increasing their production capacity. In fact, STL was forced to delay the commissioning of its new capacity of \*\*\* KFKM (which is not considered in the above table) because of lack of orders in the domestic market. However, this capacity has now been commissioned and is ready to be used from August, 2019, thereby further reducing the capacity utilization from August' 2019 onwards.

#### e. Employment

The applicants have submitted that there has not been any substantial change in employment levels during the POI.

Locations	2016-17	2017-18	2018-19	Jan-June'19
STL, Waluj (Trend)	100	110	110	107
STL, Shendra (Trend)	100	201	167	153
BFL (Trend)	100	112	112	110
Total DI Employees (Trend)	100	125	120	115

However, in view of the reducing market share and capacity utilization, the applicants have claimed that they have shut-down a part of their manufacturing capacity in Quarter2' 2019-20 (July 2019 to September 2019), and had to lay-off some of their work-force.

#### f. Productivity

Productivity has marginally declined in the most recent period due to decrease in production.

Productivity	2016-17	2017-18	2018-19	Jan- June'19 (annl.)
DI Production	***	***	***	***
Trend	100	114	120	103
Employees	***	***	***	***
Trend	100	125	120	115
Productivity	***	***	***	***
Trend	100	90	99	89

#### g. Profit/loss

The profitability of the domestic industry has declined in 2018-19 as compared to previous year, 2017-18 and they are running in losses in the most recent period. Due to imports coming at such lower prices, the domestic industry is not able to earn reasonable return/profit. The profit/loss trend, as claimed by the DI, during the POI is as below:

*fig. in Trend*

	2016-17	2017-18	2018-19	Jan- June' 19
DI Wt. Avg. Unit Selling Price (Non-captive/Non-related)	100	117	121	82
DI Wt. Avg. Cost of Sale	100	103	112	118
DI Profit/ Loss	100	173	158	(65)

The above table depicts that during the most recent period, the applicants were forced to sell at prices substantially below their cost of sales, thereby suffering huge losses. Due to imports coming at very low prices in the most recent period, especially Quarter 1 of 2019-20, the applicants were not able to increase their prices inspite of increase in cost of sales, and have been forced to accept offers below their cost. The quarterly analysis of profitability as submitted by the DI for the last 4 quarters is as below:

Profit/Loss	Q2' FY 18-19	Q3' FY 18-19	Q4' FY 18-19	Q1' FY 19-20
STL (Trend)	100	99	11	(60)
BFL (Trend)	100	(36)	(144)	(200)

#### h. Price Underselling, undercutting and Price suppression

Price Underselling, undercutting and Price suppression is shown in the table below:

*Fig.- In Rs/ FKM*

Per Unit	Jan- June 2019
DI- Weighted Avg. Unit Selling Price (SP)	***
Weighted Avg. Fair Selling Price (FSP)	***
Landed Value (Rs/KFKM) (LV)	411
Price Undercutting (SP-LV)	(***)
Price Underselling (FSP-LV)	***
Price Suppression	***

In the most recent period, the landed price of the subject goods is significantly below the level of Fair Selling Price of the domestic industry. This shows that the imports are suppressing the prices of the domestic industry, making it unviable for them to continue in the domestic market.

On the point of negative Price undercutting, the DI has submitted that they have credible market information that the exporters have been providing longer credit period or huge volume discounts to the importers. The same will be examined by the Director General as per the responses received from the exporters and importers. The Director General also noted that the DI is getting a selling price of Rs. \*\*\* per FKM against the fair selling price of Rs. \*\*\* per FKM and such selling price is much below the cost of sales and fair selling price of DI for the PUC. Thus, the price undercutting is slightly negative due to huge price suppression. However, for preliminary injury analysis, the import prices indicated in DGCIS data has been considered.

#### i. Inventory

The table below depicts the inventory levels which have witnessed a significant increase during the POI.

*fig- In Trend*

Financial Year/Quarter	Inventory (STL)	Inventory (BFL)	Total DI
2016-17	100	100	100
2017-18	79	67	73
2018-19	567	171	356
Jan'19 to June'19	588	193	377

The applicants have submitted that generally they maintain production in line with the projected sales, so as to avoid costs associated with maintaining high inventories. Consequently, it would normally have limited stock available. However, due to onslaught of imports, many customers of the applicants have refused to honour their contracts, leading to high inventories. Moreover, reducing production has led to building up of huge raw material (preform) inventory with BFL.

## 8. Threat of serious injury

**8.1** Applicants have submitted that in addition to serious injury being faced by them, the analysis of the data for the most recent period and POI clearly indicates that the Indian domestic industry is also facing an imminent threat of further serious injury.

**8.2** The Safeguard measures are governed by Article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which permits the imposition of safeguard measures to protect industries that exhibit serious injury or threat of such injury due to "increased quantities" of imports. In consonance therewith, the Section 8B sub-section (1) of the Customs Tariff Act, 1975, also provides for imposition of safeguard duty by the Central Government on an article which is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry. Thus, under both the GATT and the municipal laws, a Safeguard measure can be imposed even in cases where there is an imminent threat of serious injury to the domestic industry.

**8.3** Threat of serious injury has been interpreted as a threat that is clearly imminent as shown by facts, and not based on mere allegation, conjecture or remote possibility. The claim of threat of injury is a preventive mechanism whereby the investigating authorities are prompted to act before the actual serious injury is inflicted on the domestic industry.

**8.4** As per Article 4.1(b) of Agreement on Safeguards, "*threat of serious injury*" shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2. The Applicants have submitted that imminent threat of serious injury is evident from analysis of data for the POI as well as for the most recent period, i.e. January- June, 2019. The domestic industry vide their letter dated 03.10.2019 has submitted data relating to Quarter 2' 2019-20 also, which shows a further decline in their condition.

**8.5** From the analysis of the data, it is noted that the imports have increased very significantly from 1903 KFKM in 2016-17 to 7066 KFKM in 2018-19, and have continued to be at increased levels in April 2019 to June 2019 (6,534 KFKM, annl.). It is seen that even though there is a very marginal dip in imports in the most recent period (annualised), but on account of their drastically low prices, i.e. Rs. 375/FKM as against Rs. 603/FKM in 2018-19, they have in effect caused even more injury to the domestic industry. The continued surge in imports coupled with their decreasing prices, has impacted domestic sales and market share of both the Domestic industries, which has significantly declined during the most recent period. The applicants have claimed that their sales have decreased inspite of substantial reduction in their prices. The condition in Quarter 2 of 2019-20 again looks abysmal, and the customers are now negotiating at prices below Rs. 270-280 per FKM, which is substantially below the cost of production. The capacity utilization of the domestic industry has also declined significantly during the most recent period, and has further reduced in Quarter 2' 2019-20. Further, the impact of low priced imports is now threatening to affect Domestic industry's captive sales for manufacturing downstream product, i.e. cable, also.

**8.6** In US – Lamb, the Panel has held the analysis of USITC qua threat of serious injury as flawed because it was not "prospective", that is, it was based on past data, instead on projections as to how the industry was likely to perform in the immediate future. The panel therein drew some inferences on how to conduct a threat analysis, as follows:

*"A threat determination needs to be based on an analysis of objective and verifiable data from the recent past; These recent past facts need to be complemented by fact-based projections concerning developments in the industry's condition, and concerning imports, in the imminent future; and lastly - that the analysis needs to determine whether injury of a serious degree will actually occur in the near future unless safeguard action is taken."*

**8.7** The Applicants have submitted that the data for the most recent period clearly shows that the Indian domestic industry is already facing serious injury. The profitability of the Applicants has been completely eroded, and the imports are coming at such un-remunerative prices/ terms that the Indian industries are not in a position to compete with the import. The present trend indicates a clear evidence of imminent threat of further injury to the domestic industry. To substantiate their claim of market trends, the applicants have also relied upon the analysis and projection of the industry condition done by CRU (May, 2019 report), wherein it was stated as below:

*"Price collapse in China feeding into overseas markets*

*With prices falling to historical lows in China, domestic manufacturers are increasingly seeking export opportunities to support current production levels and higher utilisation at existing plants. Chinese exports of both bare fibre and cable have increased significantly over the last few months. Indeed, CRU estimate exports on a value basis to have jumped 110% and 22% respectively in Q1 2019 compared to the same period last year.*

*As shown in the chart below, Chinese bare fibre exports to Europe have surged 149% y/y in Q1. Meanwhile, exports to India have risen five-fold. CRU understands much of this material is being offered at highly competitive rates, in line with weak domestic pricing, and causing significant pressure on prices in both target markets. For instance, CRU have heard of offers as low as \$4.50 /F-km or below to India and Mexico. With Chinese exports likely to remain at this elevated level near-term, CRU expect continued pressure on prices globally throughout much of this year.”*

**8.8** The analysis and projections done by CRU based on the most recent data i.e. Quarter 1, of Calendar year 2019-20 (i.e. January 2019 to March 2019) clearly indicates that the Indian domestic industry is facing imminent threat of serious injury. It has been stated in the said report that with slowdown in Chinese market, imports to India from China has risen 5-fold and are coming at low prices. Further, the slowdown in Chinese market has put pressure on Fibre industry globally.

**8.9** The data of the most recent period, i.e. Quarter 4 of FY 2018-19 and Quarter 1' FY 2019-20, shows a considerable decline in applicants' financial condition. The surge in imports at lower landed cost has substituted the domestic market. In addition, the slump in Chinese market has caused global over-capacity of Optical Fibre, forcing manufacturers in other countries also to look for non-Chinese export markets. Thus, on preliminary analysis, threat of serious injury is imminent in present circumstances, wherein the Indian industries would not be able to survive unless an adequate safeguard is provided to them to fight the onslaught of imports.

## **9. Critical Circumstances**

**9.1** The Applicants have submitted that in addition to the serious injury being faced in the most recent period, i.e. January' 19 to June' 19, the condition of the domestic industry has further worsened in Quarter 2 of 2019 -20 (i.e. July- September' 2019). The capacity utilization of STL has substantially decreased to \*\*\* in Quarter 2' 19-20 from \*\*\* in Quarter 2 of 2018-19. The Capacity Utilization of BFL has also substantially decreased to \*\*\* in July- August' 2019 as against \*\*\* in Quarter 2 (July – September)' 2018. Further, the inventory with the Applicants has also remained at significantly high levels, in-spite of reducing production substantially.

**9.2** The Applicants have further submitted that the selling price of the Domestic industry has declined significantly in the most recent period as also Quarter 2 of 2019-20. The average selling price of PUC of STL has also significantly declined from Rs. \*\*\* per FKM in Quarter 2' of 2018-19 to Rs. \*\*\* per FKM in Quarter 2' of 2019- 20. In case of BFL the average selling price of PUC has also significantly declined from Rs. \*\*\* per FKM in Quarter 2 of 2018-19 to Rs. \*\*\* per FKM in July 2019 – August 2019. Thus the losses of the Domestic industry has further increased in July- August' 2019 and the condition of both the Applicants has become more critical in Quarter 2. It has also been submitted by the applicants that in order to remain viable, both the domestic producers were forced to lay off a part of its work-forces in Quarter 2' of 2019-20.

**9.3** The Applicants have further submitted that the Import prices have drastically gone down in July – August' 2019. As against average CIF Price of Rs. 603/FKM during 2018-19 and Rs. 375/FKM during January to June 2019, the Applicants have highlighted some of the import transactions in Quarter 2' of 2019-20, where import prices are even below Rs. 280/FKM Level.

**9.4** The Applicants have also submitted that given the current market situation, STL has currently closed production from most of its draw towers in its Waluj Plant. The new capacity commissioned in August' 2019 at Shendra is also running at very low capacity utilization. Even BFL has practically stopped production, as is evident from its capacity utilization significantly going down in July- August' 2019.

**9.5** From the analysis of the data submitted, it can be seen that the domestic industry is not able to compete with the low priced increased imports. It is noted that there is significant decline in domestic sales as well as average selling price of the Domestic industry. Due to lack of orders in the domestic market, the Domestic industry is not able to achieve the desired level of capacity utilization which is essential for remaining viable. Thus, the increased imports have caused and are threatening to cause serious injury to the

Domestic industry, and the condition of Domestic industry is very critical where delay in granting immediate protection in the form of provisional safeguard measure would cause irreparable damage to the industry.

#### **10. Causal Link between Increased Import and Serious Injury / Threat of Serious Injury**

**10.1** The WTO Panel on Korea-Dairy set forth the basic approach for determining “causation”, as follows:

*“In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.”*

**10.2** The analysis of data for the period 2016-17 to 2018-19 and January- June’ 2019 indicates that imports of the PUC have remained at significantly higher levels and also the import prices of the PUC have come down drastically in the most recent period. This has led to the DI revising their own prices downwards in the most recent period, leading to losses. As a result, the net sales realization of the DI has sharply declined when compared to previous quarters and the base year and previous year.

**10.3** Under these circumstances and based on the above analysis, it is preliminarily concluded that there appears to be a causal link between sudden surge in imports and the injury (and threat thereof) being caused to the DI. The period of decline in market share of the DI, sales (volume as well as price), capacity utilization and profitability etc., directly coincides with the period when there was a sudden and significant surge in imports. There is a complete substitution of DI’s market by imported product, which has caused and is threatening to cause further injury to the DI. Thus, a comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury is being caused to the DI and is likely to continue in future by the significantly increased and continually increasing imports of the PUC at alarmingly low import prices. All relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on determining the causation of serious injury to the DI have been preliminarily evaluated.

#### **11. Adjustment Plan**

**11.1** The applicants have submitted an adjustment plan to enable them to achieve more cost efficiency by better utilization of raw material, reduction in cost of procurement of raw material and removal of bottlenecks (if any) in the production process.

**11.2** The Director General notes that the aforesaid adjustment plan will be examined during the remainder of investigation.

#### **12. Public Interest**

**12.1** The requirement to analyse whether imposition of Safeguard measure would be in public interest flows from Article 3.1 of the Agreement on Safeguards, which states as follows:

*“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”*

**12.2** Though Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, do not require an examination of public interest, the public interest has been consistently evaluated before recommending the levy of definitive safeguard duty in terms of

Article 3.1 of the Agreement on Safeguards. The same will be evaluated during the remainder of investigation after receipt and examination of responses from interested parties.

### 13. Preliminary Findings

**13.1** To sum up, during the period of investigation there was an overall deterioration in the functioning of the DI. Moreover, the trend of the deteriorating parameters is indicative of the serious injury and continuing threat of serious injury in future. The parameter-wise finding of the serious injury suffered by the DI on account of enhanced imports of the PUC is summarized as under:

- a) The volume of imports of the PUC have increased significantly and are continuing to be at increased level both in absolute and relative terms;
- b) The DI's market share has declined, whereas the market share of imports has increased;
- c) The increased imports of the PUC have substituted for the market share of DI;
- d) The capacity utilization has decreased significantly despite increase in demand;
- e) The Domestic sales of the DI has declined significantly during the most recent period, and their market has been completely taken over by the imports;
- f) The DI has now shut-down a part of their manufacturing facility and now running at very low capacity utilization
- g) The DI have been forced to lay-off their work force in Quarter 2, 2019-20;
- h) The productivity per employee of the DI has shown a declining trend;
- i) The DI which were earning profit in 2017-18 are now experiencing significant losses;
- j) The inventories of the PUC have significantly increased within the DI; and
- k) There is significant price underselling and price suppression by the imported PUC.

**13.2** It is relevant to note that the DI continue to suffer serious injury and are facing further threat of serious injury. The trend in import volumes suggests that imports of PUC are likely to increase in future. Thus, an imminent threat of serious injury is also found in this case.

**13.3** In view of the above analysis, it was noted that there is a direct correlation between the increase in imports and serious injury already suffered by the DI. Various indicators suggest that the increased imports, which are continuing to increase and are at decreasing prices, are threatening to cause serious injury to the DI in the coming days. Thus, critical circumstances exist requiring imposition of provisional Safeguard Duty immediately in order to save the DI from further serious injury which would be difficult to repair, if the application of this Safeguard measure is delayed. These are, of course, preliminary findings on the basis of the documents and information on record and if any other factors that have a material bearing come to light during the course of investigation, they would be examined in detail in the due course.

### (F) Developing Nations

Proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975 provides that Safeguard Duty shall not be imposed on article originating from a developing country so long as its share of imports does not exceed 3% of the total imports of that article or, where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such developing countries, each with less than 3% import share taken together, does not exceed 9% of the total imports of that article. Further, Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016 specifies the developing countries for the purposes of this provision. Upon applying this legal provision read with the said notification to the available data in the present case, the finding is that import of the PUC is originating from more than one specified developing country including China PR. However, as a percentage of the total imports of the PUC into India, the imports from China PR individually account for more than 3% while the share of every other developing country is individually less than 3%. Also, the collective share of the developing countries whose individual share is less than 3% does not exceed 9% of the total imports of the PUC into India. Therefore, it must be held that the import of the PUC originating from developing countries (except China PR) will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

**(G) Recommendations**

14. In view of the aforementioned analyses and findings, the Director General preliminary concludes that the product under consideration viz. “Single Mode Optical Fibre” is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the DI manufacturing like or directly competitive products. The Director General further concludes that existing critical circumstances justify the immediate imposition of a provisional Safeguard Duty in order to save the DI from further serious injury, which would be difficult to repair, if the application of the provisional Safeguard measure is delayed. Accordingly, the Director General makes the following recommendations:

- i. Considering the weighted average Fair Selling Price of the Domestic Industry arrived on the basis of cost plus a reasonable return and the present average import prices, the injury margin of \*\*\* has been determined. The Director General has noted that in July 2019 and August 2019 the import prices of PUC have further reduced to Rs. 280 per FKM. As a result, the injury margin is likely to further increase if the import prices of second quarter of 2019-20 are considered. Therefore, considering the critical circumstance and the extent of serious injury, pending final determination of rate of safeguard duty, a provisional Safeguard Duty of **25 %** is proposed to be imposed *ad valorem* on CIF price on the imports of the PUC viz. “Single Mode Optical Fibre” falling under Customs Tariff Item 9001 10 00 of the Customs Tariff Act, 1975 from all countries with the exception of the developing countries indicated in clause (iii) below. The Tariff Item mentioned herein is indicative only and the description of the imported goods will determine the applicability of the provisional Safeguard Duty..
- ii. The provisional Safeguard Duty on the import of the said product, as above, is proposed to be levied for a period of 200 days (two hundred days).
- iii. As the imports from the developing countries listed in Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016, other than China PR, do not exceed 3% individually and 9% collectively, the imports of . “Single Mode Optical Fibre” originating from such developing countries (other than China PR) will not attract the provisional Safeguard Duty in terms of first proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

**H. Further Process**

15. The following further procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- i. The Director General invites comments on preliminary findings from all known interested parties within 21 days from the date of issue of preliminary findings. The comments received from them would be examined in the final findings.
- ii. The Director General would conduct oral hearing to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings.
- iii. The date of the oral hearing would be announced separately on the DGTR website (dgtr.gov.in).
- iv. The Director General would conduct verification to the extent deemed necessary.

SUNIL KUMAR, Special Secy. & Director General (Safeguard)